MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (2) (h) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority for a term of four years, subject to the other provisions of the said Act, *vice* Shri Jagannath Phadia resigned."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now we adjourn and meet at 2.00 P.M.

13.10 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at Seven Minutes Past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

SUPREME COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL*

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958."

The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

14.07-½ hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE AND INDIAN RAILWAYS (AMENDM/NT) BILL

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करने के पहले एक निवेदन करना चाहता हूं । आप आर्डर-पेपरपर देखेंगे कि मेरे प्रस्ताव और इस विधेयक पर बहस एक साथ रखी गई है । लेकिन इस विधेयक पर मेरा एक संशोधन भी है, मैंने रूल 109 के अन्तर्गत एक मोशन भी दिया है—

"That the debate on the Indian Railways (Amendment) Bill be adjourned.".

MR. DEPUTY SPEAKER: He can do that later on, after the Minister has moved the motion. Now he will speak on the resolution.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय-मैं नियमों को लेकर आपका मार्गदर्शन चाहता हूं । यह प्रश्न इस तरह से आया है कि एक तरफ तो आर्डिनेन्स है जिसकी डिसएप्रवल पर मेरा प्रस्ताव है, दूसरी तरफ विधेयक है, जिस पर बहस होनी है, इस पर मेरा मोशन है कि इस बहस को एडजर्न किया जाए, यह मैंने रूल 109 में दिया है, जो कि मेरे प्रस्ताव पर लागू नहीं होता है ।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): You can appreciate the difficulty. This resolution seeks to disapprove of the ordinance. The hon. Member would like to condemn the

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 28-11-68.

**Introduced with the recommendation of the President.

[Shri R. D. Bhandere]

ordinance. Therefore, he would like to speak on it by separating it from the Bill. Otherwise, the resolution would not survive. This resolution seeks to abrogate the oridnance *in toto*.

SHRI S. KUNDU (Balasore): The position is like this. This is a very important Bill in the sense that it is going to take away the various rights given to the workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member is going into the merits now.

SHRI S. KUNDU: I am not going into the merits. Once we raise the consitutional invalidity of this Bill, then it cannot be considered here unless the motion to the effect that it is not constitutionally valid is disposed of first. So, Shri George Fernandes's motion will have to be taken up first. Some of us also have tabled some amendments. For instance, I have tabled an amendment to the effect that the Bill be circulated and that the Attorney-General might be called to explain the constitutional validity of this Bill. Unless Shri George Fernandes's resolution is disposed of first, the hon. Minister cannot move for consideration of the Bill, nor can we discuss it. But you have clubbed together the Bill as well as the resolution. First of all you should give us an opportunity to discuss by way of points of order the question of the constitutional validity of this Bill, and after that you should give your ruling. I am sure that after you hear us, as you have been doing for the last few months, you would be convinced of what we say and thereafter there may be no occasion to discuss the Bill at all.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : म एक चीज का खुलासा करना चाहता हूं । मैं आपके सामने श्री ककधर को पेश करना चाहता हूं । यह पेज 484 है :

"If notice of a statutory resolution given by a private Member seeking disapproval of an ordinance is admitted by the Speaker, time has to be provided by Government for discussion thereof. However the resolution and the motion for consideration of a Government Bill seeking to replace that ordinance may be discussed together. When this is permitted by the Speaker, the resolution after discussion is put to vote first because if the resolution is adopted, it would mean disapproval of the ordinance and the Bill would automatically fall through. If the resolution is negatived, the motion for consideration of the Bill is then put to vote and further stages of the Bill are proceeded with. Similarly, a resolution seeking disapproval of an ordinance and a motion on a cognate matter can be discussed together."

तो मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है कि मेरा जो प्रस्ताव है उस पर बहस होकर अगर सदन उसे स्वीकार कर ले—यह चीज कभी कभी हो जाती है क्योंकि आदमी थोड़े रहते हैं—तो फिर विधेयक वाली बात आनी नहीं है, वहीं पर मामला खत्म हो जाता है । आपने विधेयक और मेरे प्रस्ताव को एक साथ रखा है यानी विधेयक पर बहस को आगे बढ़ाया जाये, एटार्नी जनरल को बुलाने के बारे में और बिल को सर्कुलेट करने के बारे में सारी चीजें आगे आ जायेंगी जब कि मेरा प्रस्ताव नियम 109 के अन्तर्गत जो है उस पर पहले बहस होनी चाहिए क्योंकि मैं तो इस विधेयक पर बहस ही नहीं चाहता हूं । इसलिये वह प्रस्ताव सदन के सामने पहले आना चाहिये और उस पर सदन का निर्णय होने के बाद, फिर आप चाहें तो दोनों पर एक साथ बहस चलायें या मेरे प्रस्ताव को लेने के बाद उस पर बहस चलायें । आप इस वक्त दोनों चीजें पेश कर रहे हैं । मंत्री जी बिल पेश कर चुके हैं, वह इन्ट्रोड्यूस हो चुका है, उस पर

बहस को आगे बढ़ाना चाहते हैं । इसलिए इस बारे में मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: As the hon. Member has pointed out already, he is supposed to move his resolution first. Formally, the hon. Minister has introduced his Bill but he has yet to place before the House the consideration motion together with his reasoning about it. In case the hon. Member's resolution is adopted by the House, automatically the hon. Minister would be debarred from proceeding further with his Bill.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : 109 का कब आयेगा ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: After the hon. Minister's speech, if he feels it necessary and the House also feels it necessary, I shall permit him to speak.

SHRI S. KUNDU: I would like to have one thing made clear from the beginning itself. Otherwise you may not permit me later on to raise it. There is an amendment to the effect that the debate on the Bill be adjourned. When that motion is discussed, various questions will come up. I have raised the question of constitutional validity of this Bill. I feel that this Bill cannot be discussed at all. So, I would request you to keep this in mind. I can wait for the hon. Minister's speech and then I can speak on it. Let the hon. Minister make his speech and then I shall make my points.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member will get an opportunity afterwards.

Now, 3 hours have been allotted for this. So, we should have some time-limit for speeches. So, hon. Members should be very brief.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 10) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 14 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने जो अध्यादेश 14 सितम्बर को जारी किया उसका पहला वाक्य यह है :

"Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to takt immediate action".

यह उसका पहला वाक्य है । आप जानते हैं यह ज. अध्यादेश आया, वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ज हड़ताल 19 सितम्बर को होने वाली थी, उ हड़ताल के सिलसिले में आया । हड़ताल जिन मांगों को लेकर हुई वह म ग सरकार के सामने एक बर सेभी ज्यादा समय से पड़ी हुई थीं । हड़ताल करने के सम्बन्ध में सरकार को जो इत्तला देनी चाहिए थी वह इत्तला हड़ताल होने से एक महीना पहले कानूनी रूप से सरकार के पास आई थी । उसके पहले सरकार जानती थी कि 19 सितम्बर को हड़ताल होने वाली है । यह जानते हुए कि हड़ताल के बारे में नोटिस आई हुई है और सरकार अपनी नीति को भी जानते हुए कि हम मांगों को मूंजर करने नहीं जा रहे हैं, वह 14 सितम्बर तक चुप बैठी रही । हड़ताल होने से सिर्फ चार दिन पहले सरकार ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि आप अध्यादेश जारी करें, इंडियन रेलवेज ऐक्ट में संशोधन के रूप में कुछ नये प्राविजन्स लायें, मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र का एक घोर अपमान किया गया है । आप जानते हैं कि इस सदन की बैठक 30 अगस्त तक चली,

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

हड़ताल की नोटिस सरकार के पास 19 अगस्त को आई थी, उस वक्त से लेकर 30 अगस्त तक यानी दो हफ्ते सदन की बैठक चलती रही और सरकार कम से कम अपने मन को जानती थी कि हम अपने कर्मचारियों की मांगों को मानने नहीं जा रहे हैं तो फिर उस हालत में अगर रेल कर्मचारियों का मुकाबला करने के लिए या कोई दूसरे कर्मचारियों का मुकाबला करने के लिये किसी भी नये कानून की जरूरत पड़े तो उसके लिये इस सरकार का फर्ज था कि इस सदन के सामने आती और इंडियन रेलवेज ऐक्ट में जो भी संशोधन करने थे वह पेश करती । लेकिन यह सरकार इस सदन के सामने खड़े नहीं होना चाहती थी, रेल कर्मचारियों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर सदन में बहस नहीं करना चाहती थी । सरकार ने एक फासिस्ट मनोवृत्ति अपनाई हुई है, वह हर रोज फासिस्ट तेवरों का इस्तेमाल करना चाहती है इसी लिए उसने 14 सितम्बर तक कोई कदम न उठा कर उसके बाद राष्ट्रपति को सलाह देती है कि अध्यादेश जारी करिये । फिर 19 सितम्बर को, अच्छी या बुरी, वह हड़ताल हुई । राष्ट्रपति का अध्यादेश जो 14 तारीख को निकला उसके ऊपर हम में से बहुत से लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया । फिर सरकार ने अध्यादेश के जरिये से अपने ही कर्मचारियों को और उनके संगठन को जो कुचल डालने का प्रयास किया और 19 सितम्बर को जो घटनायें घटीं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम समझते थे कि यह सरकार इस अध्यादेश को वापिस लेने का काम करेगी क्योंकि पहली बार ही यह काम नहीं हुआ है बल्कि सन् 60 में जब हड़ताल हुई थी तब भी एसेंशियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स आर्डिनेन्स आया था । उस वक्त भी रेल कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों पर बंधन लगाने वाला अध्यादेश आया था लेकिन उसको कानून का रूप देने का काम सरकार ने नहीं किया था । संविधान में यह दिया हुआ है कि अध्यादेश निकलने के बाद अगर सरकार चाहे तो राष्ट्रपति को उसे वापिस लेने की सलाह दे सकती है । 123(2)(बी) कहता है :

> "An Ordinance promulgated under this article shall have the same effect as an Act of Parliament, but every such Ordinance may be withdrawn at any time by the President."

तो जिस काम के लिये आप ने अध्यादेश जारी किया वह काम पूरा होने के बाद, हड़ताल को कुचल डालने के बाद, रेल कर्मचारियों पर गोली चलाने के बाद और अपनी हुक्मशाही मनोवृत्ति को दुनिया के सामने पेश करने के बाद कम से कम आप को इस अध्यादेश को वापिस लेने की सलाह राष्ट्रपति को देनी थी लेकिन उसके खिलाफ आप उस अध्यादेश को कानूनी रूप देने की कोशिश यहां कर रहे हैं । मेरी राय में यह सिर्फ प्रजातंत्र पर ही हमला नहीं, बल्कि यह सरकार तानाशाही के रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहती है । इसीलिए आज ऐसा कानून बनवाने के लिये यह सरकार इस सदन के सामने आई है । रेलें सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं हैं बल्कि सारी दुनिया में हैं । हम लोग तो अभी अभी इंजन बनाना शुरू किये हैं जिसका ज्यादातर माल अभी भी विदेशों से ही आता है । यह हड़ताल सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं हुई और जगहों पर भी ऐसी हड़तालें होती हैं । सुबह यहां पर एक प्रश्न था लेकिन जिनके नाम पर वह प्रश्न था, श्री कछवाय, वे यहां पर उपस्थित नहीं थे । एक सत्र के बीच में मंत्री लोग कहां कहां विदेशों का चक्कर लगाते हैं, उसकी मालूमात सदन में होनी ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : लाखों रुपये खर्च करके मंत्री लोग विदेश जाते हैं । प्रधान मंत्री का तो और कुछ काम ही नहीं है, एक सत्र खत्म हुआ तो विदेश यात्रा के लिये तैयार रहती है । और जब सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

चली तो वह यहां से विदेश चली गयीं। और मुल्कों में भी रेलें चलती हैं, सरकारी नौकर हैं, वे लोग भी हड़ताल पर जाते हैं इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिये। प्रधान मंत्री अभी जब दक्षिण अमरीका की यात्रा पर थीं तो चिली में उनको जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि सरकार वहां की हट गयी और हमारी प्रधानमंत्राणी को पहले देश में ही आराम करना पड़ा। तो दुनिया में क्या हो रहा है, नागरिक अधिकार जो लोगों के रहते हैं वे अधिकार किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में सरकार को जानकारी होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, 4 दिन पहले इटली में हड़ताल हो गई। 48 घंटे के लिये इटली की रेल गाड़ियां बन्द रहीं और उसका नतीजा यह हुआ कि इटली की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और 20 वर्षों के इतिहास में पहली बार वहां समाजवादी नेता को प्रधानमंत्री होने के लिये वहां के राष्ट्रपति ने बुलाया। आप लोग तो समाजवादी हो ही। तो इटली का उदाहरण मैंने इसलिये आपको बताया कि रेल कर्मचारियोंकी हड़ताल हिन्दुस्तान में ही नहीं होती है, दूसरे मुल्कों में भी होती है और इटली में रेल कर्मचारियों की हड़ताल से वहां की सरकार गिर गयी। इंगलैंड में भी हड़तालें होती हैं। अमरीका में तो रेल कम्पनियां निजी क्षेत्र की हैं और लगातार वहां पर रेल उद्योग में हड़ताल होती रहती है। लेकिन उन हड़तालों को रोकने के लिये कोई अध्यादेश जारी करना, लोगों पर गोलियां चलाना और उन अध्यादेशों को फ़ासिस्ट ढंग से कानून बना कर सदन के सामने लाना, ऐसा उन देशों में जहां प्रजातंत्र की गम्भीरता लोग जानते हैं, नहीं होता है। आप इस अध्यादेश को देखिये। यह साल है ह्यूमन राइट्स ईयर, और भारत में पता नहीं कितने करोड़ रु० आप खर्च करने जा रहे हो गांधी शताब्दी मनाने में, जिन्होंने पहली बार हिन्दुस्तान में सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह सरकार आज पहली बार उस सत्याग्रह को क्रिमिनल आफ़ेंस घोषित करने जा रही है इस अध्यादेश के जरिये। आर्डिनेंस के पहले ही पन्ने पर लिखा है :

"Obstructing running of train, etc. If a railway servant, when on duty or otherwise, or any other person obstructs or causes to be obstructed or attempts of obstruct any train, rail-car or other rolling stock upon a railway, by squatting picketing, keeping without authority any rolling-stock on the railway or tampering with signal gear or otherwise, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both."

अब यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है 'स्क्वेटिंग और पिकेटिंग दी रेलवे ट्रैक'। यह आज गुनाह हो रहा है, जिसके लिये दो साल की सजा दी जा सकती है या 500 रु० जुर्माना हो सकता है, या दोनों। पता नहीं जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब हमारे रेल मंत्री को पटरी पर बैठने का मौका मिला था या नहीं। मैं नहीं जानता कि डा० राम सुभग सिंह को मौका मिला था कि नहीं, लेकिन हिन्दुस्तान के लाखों लोग रेल की पटरी पर बैठ कर, गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर चल कर, हाथ में लाठी को न लेते हुए.....

डा० राम सुभग सिंह : हमारे यहां सारी पटरियां उखाड़ी गयी थीं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मुझे पता नहीं उन्होंने यह काम किया था या ऐसे काम करने वालों का समर्थन किया था। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने यह जरूर कहा था कि हिंसा मत करो। न प्राण हानि हो, न माल हानि हो और प्राण हानि न करते हुए जो सिविल नाफ़रमानी कर सकते हो वह करो। यह गांधी जी

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

का बताया हुआ रास्ता था और यही लेकर लाखों की तादाद में उन दिनों के नौजवान रेल की पटरियों पर जाकर बैठे थे, लेटे थे, मारे गये थे और आज उसी का यह फल है कि इस सरकार को यहां बैठने का मौका मिला और आज यह सरकार काम कर रही है, इतनी गिरावट हो गई दिमागी कि सारी नैतिकता खत्म हो गई और पिकेटिंग को क्रिमिनल आफेंस घोषित करने जा रही है। अगर कोई हमारे ऊपर अन्याय होता हो रेलवे की ओर से तो उसका प्रतिकार करना भी एक गुनाह कर के यह सरकार घोषित करने जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप एक बात मानेंगे कि कोई मजे में रेल की पटरी पर नहीं लेटता है, गाड़ी के सामने पिकेटिंग का काम नहीं करता है। अन्याय होता है तब उसके प्रतिकार के लिये ये चीजें होती हैं। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान की रेलें कैसे चलती हैं? मैं तो कह चुका हूं कि रेलवे अपनी जो जिम्मेदारी है उसको कभी नहीं पूरी करती। दिल्ली स्टेशन पर रेल मंत्री मेरे साथ चलें, जो आपका एयर कंडीशन्ड मैलून है उसमें नहीं, बल्कि थर्ड क्लास के डिब्बे में, आप देखेंगे कि बत्ती नहीं जलती है, पंखा नहीं चलता है, पानी नहीं मिलता है, गाड़ी भी कभी समय पर नहीं निकलती है, और समय पर नहीं आती है। अब आप बतायें मैंने तो 30 रु० का बम्बई से दिल्ली आने का टिकट खरीद लिया लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि गाड़ी समय पर क्यों नहीं चलती है तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता है, पानी और रोशनी नहीं है। अब अगर मैं उस वक्त यह फैसला करता हूं मुल्क के एक नागरिक की हैसियत से, गांधी जी ने जो हमें कहा था कि जहां अन्याय दिखाई दे तो उसका प्रतिकार करो, तो मैं सिविल नाफरमानी करने के लिये नीचे उतरता हूं, गाड़ी की चेन खींचता हूं पटरी के सामने खड़ा हो कर कहता हूं कि मैंने टिकट में पैसा दिया है मुझे पंखा, पानी चाहिये, बिजली चाहिये और आप नहीं देते हो और जब तक यह सुविधा नहीं दोगे तब तक तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी, अगर ऐसा कहूं तो क्या गुनाह होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सात दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट ने टेलीफोन का टैरिफ गैर कानूनी घोषित किया। उसने यही तो कहा था कि जब लोगों से पैसा लेते हो तो उसके बदले में जितनी सुविधायें उनको देनी चाहिये वह देना भी तो तुम्हारा फर्ज है और उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हो। यह अन्याय लोगों के ऊपर मत करो। आपको जो पैसा देता है किसी भी सेवा के लिये तो उतनी सेवा करो, उससे ज्यादा न पैसा लो न उससे कम उनकी सेवा करो। यही अदालत का कहना रहा, जो नैचुरल जस्टिस हो वह करो। हिन्दुस्तान की अदालतों ने आज तक जो भी निर्णय दिये नागरिक अधिकारों को लेकर उनका मतलब यही तो है कि जहां अन्याय है उसका मुकाबला होना चाहिये। अब अगर किसी दूर देश पर रेल गाड़ी में वह सुविधा नहीं मिलती है जिसका मैं हकदार हूं तो क्या डाक्टर साहब या माननीय पुनाचा जी यह चाहेंगे कि मैं कलकत्ते में जाकर अदालत में शिकायत करूं? अथवा आप यह पसन्द करेंगे कि गांधी जी के बताये हुए रास्ते के अनुसार गाड़ी से नीचे उतर आऊं और यह कहूं कि मुझ पर होने वाले अन्याय को तुरन्त दूर करो।

अब आप क्या करने जा रहे हैं? 100(बी) में कह रहे हैं कि:

"Any attempts to obstruct any train, rail car or other rolling stock on the railway by squat-

ting and picketing shall be an offence punishable with 2 years rigorous imprisonment or Rs. 500 fine or both."

कहां रही इन लोगों की नैतिकता, और कैसे यह अध्यादेश हमारे सामने आ सकता है जिसके अनुसार लोगों को सुविधा न देते हुए हमको फासिस्ट मनोवृत्ति का शिकार बनाने का प्रयास हो रहा है? और दूसरी तरफ रेल कर्मचारियों के बारे में कितने नियम हिन्दुस्तान में हैं? रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो नियम यहां लागू हैं मैं समझता हूं कि वैसे नियम दुनिया के अन्य किसी मुल्क में नहीं होंगे। यह तो आपको मालूम ही है कि रेल कर्मचारी किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता है और उसके ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के बारे में भी नियम बना हुआ है। लेकिन आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि कोई भी रेल कर्मचारी का रिश्तेदार, नजदीक का अथवा दूर का, वह भी अगर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बने, वह किसी राजनीतिक दल की सभा में जाय तो रेल कर्मचारी का फर्ज है कि वह दूसरे दिन अपने अधिकारी के पास जाकर कहे और उसे लिखित रूप में दे कि उस की पत्नी, बेटा, भाई, मां अथवा भतीजा अमुक राजनीतिक दल की मीटिंग में गया था। इस तरह का नियम आप लोगों ने रेल कर्मचारी के लिए बना रखा है। रेलवे कर्मचारियों की सर्विस कंडिशंस में इस तरह का नियम बना रखा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का कोई रिश्तेदार किसी भी दल की मीटिंग में हिस्सा ले, उस कर्मचारी का भाई, भतीजा अगर किसी राजनीतिक दल की मीटिंग में शरीक हो तो सर्विस कंडिशंस के मुताबिक उस रेलवे कर्मचारी को दूसरे दिन जाकर अपने अधिकारी को लिखित रूप से अपने बच्चे, बीवी या भाई, भतीजे के बारे में शिकायत करनी होगी, उसे लिखित रूप से अधिकारी के पास यह देना होगा कि उसका अमुक-अमुक रिश्तेदार कल श्री पीलु मोडी की सभा में जाकर उनका लैक्चर सुन कर घर आया है। मेरा कहना है कि इस तरह का नियम रेलवे कर्मचारियों की सर्विस कंडीशंस में लिखा हुआ है। माननीय सदस्य चाहें तो बराबर उसे पढ़ कर देख सकते हैं।

SHRI PILOO MODY (Godhra): I would like the Minister to clarify this rightway. Please clarify this rightway whether this is true or not.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): I would like to look into the matter. The only point here is that a certain information regarding political activities of certain elements has got to be brought to the notice of the authorities because that has relation in regard to safety of the railways.

SHRI J. M. BISWAS (Bankura): The Minister is not correct. According to the service conduct rules, it is mendatory on the railway employees that they would have to inform the Government if any of the relations who are not railway servants take part in any politics.

SHRI GEORGE FERNANDES: Including attendance at a meeting.

यह रेल कर्मचारियों के सर्विस और कंडक्ट रूल्स में दिया हुआ है। बीच आफ रूल करने पर रेल कर्मचारियों के लिए सजा का भी विधान दिया हुआ है। मेरा कहना है कि इस देश के रेल कर्मचारियों पर जैसे सेवा सम्बन्धी नियम लागू हैं, जिस तरह की बंदिशें उन पर लगायी गयी हैं वैसे रूल्स और बंदिशें

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

किसी अन्य प्रजातंत्री देश अथवा किसी भी देश में नहीं चलती है। अभी पिछले दिनों यह सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल सम्बन्धी प्रश्न को लेकर क्या-क्या बकवास हम लोग यहां सुन रहे थे। यहां यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारी यहां हड़ताल पर चले गये और पता नहीं देश का क्या होगा, प्रजातंत्र का क्या होगा? अब हमारे देश का प्रजातंत्र क्या इतना कमजोर है कि केवल एक दिन की सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल होने पर सारा प्रजातंत्र गिर जाता है अथवा एक दिन सदन के अन्दर प्रधान मंत्री को बोलने से रोक देने में इस देश का पूरा प्रजातंत्र खत्म हो जाता है? यह लोग क्या प्रजातंत्र की बात कर सकते हैं? मैं अपने इन मित्रों को बतलाना चाहता हूं कि फ्रांस में तीन दिन तक हड़ताल चली लेकिन वहां कोई प्रजातंत्र खत्म नहीं हुआ। यह प्रजातंत्र ऐसी नाजुक चीज नहीं है, वह एक बहुत मजबूत चीज होती है और वहां पर वह प्रजातंत्र खत्म नहीं हुआ। इसी तरह मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि जर्मनी में पलटन के लोग ट्रेड यूनियन के मेम्बर हो सकते हैं। पलटन में कर्नल के रैंक तक के लोगों को ट्रेड यूनियन का मेम्बर बनने का अधिकार है। इसी तरह जर्मनी की ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक वर्कर्स यूनियन है जो कि सबसे बड़ी वहां की यूनियन है और जिसकी सदस्य संख्या 8–10 या 12 लाख की होगी, उस में म्युनिसपैलिटी के सफाई कर्मचारियों के साथ पलटन के लोग भी उसके सदस्य हैं। इतना ही नहीं इजरायल की पलटन के जो प्रधान सेनापति हैं वह भी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय को और उनकी तरफ के लोगों को यह बतला देना चाहता हूं कि इस तरह का अधिकार वहां पर ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने का प्राप्त है और अगर वह जानना चाहेंगे तो मैं उनके नाम भी उन्हें गिना दूंगा जहां जहां कि कर्मचारियों को यह ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त है।

भारत जो कि एक प्रजातंत्री देश होने का दम भरता है वहां हालत उसके प्रतिकूल है और जैसा मैंने सदन को बतलाया रेलवे कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों को और भी कड़ा बनाया जा रहा है और उन पर नये-नये प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं जैसा कि यह 100 ए और 100-बी के जोड़े जाने से साफ़ जाहिर होता है। 100-ए में यह लिखा हुआ है:

"100A: If a railway servant, when on duty, is entrusted with any responsibility connected with the running of a train, rail-car or any other rolling-stock from one station or place to another station or place, and he abandons his duty before reaching such station or place without authority or without properly handing over such trains, rail-car or rolling-stock to another authorised railway servant, he shall be punishable with imprisonment for a term which may etxend to two years, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both."

मैं रेल मंत्री जी अथवा कानून मंत्री, जो कि इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस नये सेक्शन का जो कि इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसका मतलब भी समझा है? क्या आप इसका अन्दाज लगा सकते हैं कि इसका रेल कर्मचारियों पर कैसा असर पड़ेगा और उन पर क्या-क्या मुसीबत इसके कारण आने वाली है? उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाऊं कि मुझको जैसे रेलगाड़ी पर 5 घंटे काम करना है और रेल दिल्ली से लेकर मुझे आगरा तक अथवा अन्य किसी स्टेशन

तक ले जानी है और आगरा जब मैं रेल को लेकर पहुंचता हूं और पांच घंटे की ड्यूटी अंजाम देने के बाद मुझे वहां दूसरे रेल कर्मचारी के हाथ में इंजन सौंपना है और वह वहां मुझे रिलीव नहीं करता है, वह रेल कर्मचारी बीमार होने के नाते अथवा अन्य किसी कारणवश वहां मुझे रिलीव करने नहीं पहुंच पाता है तो आप मुझे क्या कहेंगे ? अब मैं पांच घंटे की ऐक्टिव ड्यूटी दे चुका हूं और मुझे आगे भी ड्यूटी अंजाम देते रहने के लिए यह अध्यादेश बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है कि नहीं तुम्हें 12 घंटे काम करना पड़ेगा और यह कि मुझे रेल को आगे लेकर बढ़ने पर मजबूर किया जायेगा तो मेरा कहना है कि मैं उस चीज को भी मानने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी परसों इस सदन के अन्दर रेल में सफर करने वाले मुसाफिरों के बारे में बड़ी चिन्ता प्रकट की गई थी लेकिन एक इंजन ड्राइवर को जिसे कि 5–6 घंटे ड्यूटी देने के बाद दूसरे के हाथ में इंजन सौंपना चाहिए वैसा न करा कर अगर आप उसी इंजन ड्राइवर से 12–12 घंटे की ड्यूटी लेना चाहें तो यह क्या आप रेलवे के यात्रियों की वाकई चिंता करते हैं? वह तो रेल के मुसाफिरों की चिन्ता न करके रेल मंत्री महोदय मालूम पड़ता है देश की बढ़ी हुई आबादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मकसद के लिए वह जो आर्डिनेंस उन्होंने पास करवाया था उसे अब कानूनी शक्ल देने जा रहे हैं । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर उनका दिमाग जा किस दिशा में रहा है ? यह साफ़ है कि वह जो यह नये सैक्शन 100 ए और 100 बी जोड़ने जा रहे हैं वह प्रजातंत्री सिद्धांत के प्रतिकूल है और इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन ने जो एक इसके लिए सिद्धान्त माना है उस प्रजातंत्री सिद्धांत के खिलाफ जाता है इसलिए इस अध्यादेश को यह सदन किसी भी हालत मंजूर नहीं कर सकता है ।

एक आखिरी बात मैं इस मौके पर और कहना चाहूंगा । ऐसा कानून बना कर रेल कर्मचारियों पर बहुत जुल्म किया जा रहा है । रेलवेज में 18 लाख कर्मचारी काम करते हैं हालांकि मंत्री महोदय जब बात करते हैं तो केवल 13 लाख की ही बात करते हैं तो दरअसल चीज यह है कि 5 लाख रेलवे के कर्मचारी कैजुएल हैं और उन की तनख्वाह डेढ़ रुपया, दो रुपया या ढाई रुपया होती है और चूंकि वह बेचारे कैजुएल हैं इसलिए उन का यह जिक्र नहीं करते हैं और बस हमेशा वह 13 लाख की ही बात किया करते हैं जब कि असल में रेलवेज में 18 लाख कर्मचारी काम करते हैं । हिन्दुस्तान की आबादी में हर 80 लोगों में एक आदमी रेल कर्मचारी है या रेल कर्मचारी की कमाई पर जिंदा रहने वाला व्यक्ति है । हिन्दुस्तान की रेलवेज का निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है । मुझे अफसोस है कि हिन्दुस्तान के रेलवेमैन को जिस ढंग से संगठित होना चाहिए था उस ढंग से वह संगठित नहीं हो पाये हैं । मेरी इच्छा है कि वह ठीक तरीके से संगठित हों और अगर किसी दिन वह संगठित हो गये तब रेल मंत्री महोदय को पता चलेगा कि उन की क्या ताकत है ।

हम लोग कभी-कभी हिन्दुस्तान में हड़ताल की बात किया करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि रेल कर्मचारी अभी तक हड़ताल में सम्मिलित नहीं हुए हैं लेकिन अगर रेल कर्मचारी बंद करने की ताकत रक्खें तो फिर दूसरे किसी को बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सरकार को मजदूरों और कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । यह हिन्दुस्तान के लिए एक बदनसीबी की बात है कि इस देश में रेल कर्मचारी अभी तक संगठित नहीं हो पाये हैं और दूसरी तरफ़ जो मजदूर संगठन मौजूद हैं भी उन को शासन की ओर

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

कुचलने का प्रयत्न हो रहा है और इसी दृष्टि से वह अध्यादेश लाया गया और अब उस को कानूनी रूप दिलवाया जा रहा है । इस तरह के अध्यादेशों के जरिए और इस किस्म के फ़ासिस्ट कानूनों को मंजूर करा कर क्या यह सरकार इस देश में प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहती हैं यह क्या मजदूर आन्दोलन को तरक्की देने का और हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र का बनाये रखना का तरीका है ? निश्चित रूप से यह प्रजातंत्र का गला घोंटना है और मजदूर आन्दोलन को इस देश में कुचलना है । इसलिए अंत में पुनः इस सदन से इस बात का आग्रह करूंगा कि वह इस तरह के प्रतिबंधात्मक नियमों को लागू करने की स्वीकृति सरकार को न दे और 123(2) बी के अन्तर्गत राष्ट्रपति को इस बात की सलाह दे कि यह जो नया संशोधन विधेयक सरकार द्वारा सदन में लाया गया है उस को वापिस ले लें ।

Sir, I move:

"That this "House disapproves of the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1968 (Ordinance No. 10 of 1968) promulgated by the President on the 14th September, 1968."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That this House disapproves of the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1968 (Ordinance No. 10 of 1968) promulgated by the President on the 14th September, 1968."

The hon. Minister.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): Should I reply to the points or move the Bill?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He should move the Bill first.

SHRI C. M. POONACHA: I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890, be taken into consideration."

While introducing the Bill, the hon. Member and other friends raised certain points about the constitutionality of the Bill as to whether this House is competent enough to discuss or take up a measure for consideration of this type and it was held by you that as regards the constitutional points raised by my hon. friends there was nothing in them and you ruled out the points of order.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): He did not give a ruling on the constitutional points. You should not misquote him.

SHRI C. M. POONACHA: I will refer to a few points. This Bill is well within the rights of this House and the House is quite competent enough to proceed with the consideration of this Bill. Having said so, I beg to refer to the Act that we have already in operation, namely, the Indian Railways Act, 1890...

SHRI DATTATRAYA KUNTE (Kolaba): On a point of order. If I mistake not, the hon. Minister has moved a motion that the Bill be taken into consideration. We have a motion by the hon. mover Shri Fernandes. The point really is whether the House could discuss two motions at one and the same time. The normal parliamentary practice is that there ought to be only one motion before the House...

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda): That is allowed in this House.

SHRI DATTARAYA KUNTE: I am overhearing somebody saying that it is allowed in this House. This House has some rules of business which lead to proper working of the House and that is why I am raising

this point. I really want to know, whether before one motion is disposed of the House could take up consideration of another motion. This will mean that I could move a third motion as well. It might be that they might be dealing with the same subject-matter. The motion which the hon. Railway Minister has moved is really in opposition to the motion of the hon. Member in a way. Therefore, if an amendment opposing the original motion cannot be moved, could a motion opposing the original motion be moved as well. It is not only whether two motions can be considered or not. They are also contradictory to each other. The hon. Member has moved a motion wanting to express disapproval of the House. This has happened because on the Order Paper we find that both these motions have been kept together. I should have really hoped that whoever arranged the business of this House had put them separately before the House so that the House could apply its mind more diligently. When two motions are being put before the House simultaneously, it might be that the member who wants to take part in it is in a difficulty. A Member might be there who would like to oppose the motion moved by the hon. Member Shri Fernandes and at the same time would like to oppose the Bill because the ordinance, after a lapse of time will automatically lapse and there he would tell Shri Fernandes that the Ordinance was on the 14th September and 'we will wait till it lapses' and the member would oppose the Bill at the same time.

Hon. Member Shri Fernandes has gone into the merits of this. The difficulty has arisen because both have been placed simultaneously on the Agenda Paper and we are not the authority to arrange the Order Paper. This difficulty has arisen and I want to bring it to your notice. The two motions in a way are contradictory to each other. If they are going to be disposed of like this, it creates difficulty. Therefore, I want to raise this point of order, though hon. Member Shrimati Sucheta Kripalani wants to tell me that this has been done before also. Points of order are raised to correct things. If it is said that this is the practice in this House, then we need not have any rule book at all and we should go by practices and conventions and all those things followed in the British House of Commons. The very fact that we have Rules of Procedure shows that we are supposed to abide by them and whatever is being done must be based on these rules and not on what was being done in this House, which might have been wrong. That is my point of order.

SHRI S. KUNDU (Balasore): Sir, as I explained in the beginning....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your point of order was about the constitutional validity, which is different.

SHRI S. KUNDU: It is a completely different motion saying that the debate on the Bill should be adjourned. Now, how could the Minister come forward with a separate motion that the Bill be taken into consideration, which goes in a completely different direction? Rule 109 says:

> "At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker."

So, having moved such a motion...

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already said that after the Minister has finished his speech. I will give him an opportunity.

SHRI S. KUNDU: The Minister can make a speech throughout the length and breadth of India at any time he likes; nobody can stop him. But when they are in the House they must adhere to the Rules of Proce-

[Shri S. Kundu]

dure. The motion before the House is that the debate be adjourned. Either there should be a discussion on this motion or it should be put to vote and a decision taken. Otherwise, we would be going against the Rules of Procedure.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member Shri Fernandes has placed his submission before the House. The hon. Minister places his submission before the House. Then, I will permit the hon. Member to move his motion. Of course, the House will decide whether the discussion should be adjourned or not. At this stage, let him not mix up the two issues.

SHRI S. KUNDU: The third issue I have already raised in the beginning.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have taken note of it. Now, Shri Kunte has raised another point of order and pleaded with some cogency whether both the motions could be taken up together, whether there would not be some incongruency and so on, on which I will have to give a ruling.

SHRI S. KUNDU: Sir, will you resume your seat for a minute so that we will not be called upon to sit down? Your ruling could only be to delete that portion of the Minister's speech where he says "that the Bill be taken into consideration". The Minister cannot move such a motion. He can only express his opinion without moving it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Usually the Minister begins or ends his speech with the motion "That the Bill be taken into consideration". I do not know whether the Minister has actually said it or not. The hon. Member can make his plea after the Minister has made his speech and moved his motion.

SHRI S. KUNDU: Sir, you should rule out that particular sentence, or motion, as improper at this stage. Let this motion be disposed of. Then he can introduce his Bill. Otherwise, strictly speaking, it will not be constitutional.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister wanted to say why this Bill has to be considered. He has tried to make out a case for that. He has not said anything beyond that.

SHRI S. M. BANERJEE: On the point of order raised by the hon. Member, I would like to say.....

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE: (Balrampur): Sir, are you allowing a discussion on this?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, not at all.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, I want to support you in the case of this point of order.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): He does not require any support from you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you any new points to make?

SHRI S. M. BANERJEE: The business before the House is that the disapproval motion moved by Shri Fernandes and the Bill move by the Minister be discussed together. The Business Advisory Committee, in its wisdom, has taken a decision that both these motions should be discussed together. I am a member of the Business Advisory Committee and I should say that. I request Shri Kunte to go through the parliamentary proceedings of 1960. In 1960 a similar question arose when an Ordinance was promulgated and the Ordinance and the Bill were both discussed together. I am quoting from *Shakdher*.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is with me. It was just now pointed out by Shri Fernandes.

SHRI S. M. BANERJEE: There have been such instances in the past and a convention has been developed that such motions, whether it is the Gold Control Ordinance or the Gold Control Bill or whether it is the Essential Services Maintenance Ordinance or the Essential Services Maintenance Bill, though we were against both, could be discussed together. Precedents are there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: His point of order is that apparently it looks incongruous, but because we have adopted a certain p actice in this House since 1960 I do not think there is any validity so far as this point of order is concerned. In the last session also this was done. But as he has raised a fundamental issue if he thinks that it looks incongruous, it might be taken up in the Rules Committee. So far as the practice adopted by this House is concerned, we are this time with the concurrence of the Business Advisory Committee discussing them together.

SHRI C. M. POONACHA: In accordance with article 123(2) of the Constitution it is necessary that we should come before this House to replace the Ordinance with a piece of legislation within six weeks' time after Parliament meets. Since Government have taken a decision that this Ordinance should be replaced and a Bill should be placed before this House for its consideration, action has been taken to introduce this Bill. At this stage the Bill has to be taken up for consideration and there could be no question of adjourning the debate on the Bill because within six weeks a decision on the merits of the Ordinance, whether the House would like to accept it or not, would have to be taken. Therefore at this stage I would only submit that the consideration of the Bill is urgent and necessary.

SHRI GEORGE FERNANDES: We are opposed to the Bill.

SHRI C. M. POONACHA: I shall be coming to the merits later.

As such the House has to proceed with the consideration of the Bill. I submit that the Bill may be taken up for consideration.

SHRI GEORGE FERNANDES: It will be thrown out.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Fernandes has given notice of a motion for adjournment of the debate on the Bill under rule 109.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इंडियन रेलवेज (एमेंडमेंट) बिल, 1968 पर बहस को स्थगित किया जाये।'

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर बहस स्थगित करने की मांग होगी तो वह खाली विधेयक पर नहीं होगी, श्री फरनेंडीज ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर भी होगी। अगर दोनों प्रस्ताव साथ साथ दिये जा रहे हैं और दोनों पर एक बहस हो हो रही है तो अब उनके टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं।

श्री जार्ज फरनेंडीज : इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप रूल 109 को देखिये।

"Adjournment of Debate on and Withdrawal and Removal of Bills

At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker."

मैंने जो प्रस्ताव दिया है वह 109 के अन्तर्गत है कि इस बिल पर जो बहस है उसको स्थगित रखा जाए। मेरा जो प्रस्ताव है जिस पर बहस हो रही है वह संविधान के आधार पर दिया हुआ प्रस्ताव है। दोनों अलग अलग चीजें हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I know, it is totally different.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: Sir, before you give a ruling, I must get a clarification.

Now there is a third motion. We were supposed to be debating the Resolution of the hon. Member. That was the first motion. The second motion is that the Bill be taken into consideration. Now the third motion is that the discussion on this Bill be adjourned. There are three motions. I really want to know when my turn will come to speak on the original Resolution moved by the hon. Member. I would not like to take part in the debate on the motion about taking the Bill into consideration, or the other motion asking for the adjournment of the discussion on the Bill.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI: You can confine yourself to the Bill.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: Again, the hon. Member is trying to advise me that I can confine myself to the Bill. But this will be confounding me and also her. The *obiter dicta* should not fall from her mouth.

SHRI PILOO MODY: Be chivalrous.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: I am; at one stage, I tolerated it.

This is the third motion and there would be other motions also. For instance, I move one more motion that the debate on this item be postponed to the next session. That will be another motion. I want to know whether along with the motion of the adjournment of the discussion on the Bill, you are going to take another motion that the consideration of the item be postponed to another session so that we can see in what anomaly we can land ourselves. I seek your permission to move this motion. I need not give any notice. I can move this motion at any stage of the discussion. I move:

"That the consideration of the item be postponed to the next session."

This is the fourth motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri George Fernandes has moved the motion for the adjournment of the discussion on the Bill. This is a specific motion.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But we are having a combined debate.

MR. DEPUTY SPEAKER: Yes, for convenience sake. As Shri Banerjee pointed out, we have taken both the motions together for convenience sake and to save the time of the House. Shri George Fernandes's motion is specific about the adjournment of the consideration of the Bill. So, I put it to vote. The question is.....

SHRI DATTATRAYA KUNTE: I have moved the fourth motion also.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, in the process of voting....

SHRI DATTATRAYA KUNTE: I just now said I move the fourth motion. Let me clarify the position. The first motion of Shri George Fernandes that the Ordinance be not approved by the House is not disposed of. There is another motion that the Bill be taken into consideration. There is the other motion that the discussion on the Bill be adjourned. I want to move the fourth motion that the diascussion on this item be postponed to the next session.

MR. DEPUTY SPEAKER: Under what rule?

SHRI DATTATRAYA KUNTE: The motion that the consideration of the item be postponed to the next session can be brought at any stage. I am moving the motion. I move:

"That the consideration of the item be postponed to the next session."

You can put it to vote.

MR. DEPUTY SPEAKER: You are entitled to move a motion under Rule 109. Shri George Fernandes has moved a motion asking for adjournment of the discussion on the Bill without specifying the time limit. You are only specifying the time limit. That is all.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: It is a different motion. I have moved that the consideration of this item be postponed to the next session.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA (Anand): Let us dispose of the motion of Shri George Fernandes first.

MR. DEPUTY SPEAKER: I have already ruled that this has been the practice followed in the House and it has the approval of the Business Advisory Committee that both the motions may be clubbed together for the sake of convenience and to save the time of the House. This is the main purpose. I have ruled that they will be taken together. The motion which I am disposing of first is the one moved by Shri George Fernandes Now, Shri Kunte has made a plea that he would like to move another motion.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: I have moved it.

MR. DEPUTY SPEAKER: He has moved it But, I think, under the Rules of Procedure, it is not admissible. He can point out to me a specific rule. This is not admissible.

13 hrs.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है कि बिल और मोशन साथ लिये जायें । आप ने यह भी कहा है कि हाउस में पहले यह होता रहा है । अगर माननीय सदस्य श्री जार्ज फ़रनेन्डीज, का मोशन एक्सेप्ट हो गया, तो उस के नतीजे क्या होंगे ? आप चेयर में बैठ कर केवल यही सोच कर नहीं चल सकते कि वह मोशन हाउस के द्वारा ठुकरा दिया जायेगा । अगर वह मोशन स्वीकार कर लिया गया, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि विधेयक पर तो चर्चा रुक जायेगी और खाली मोशन पर चर्चा चलेगी ? तब इस सदन की पुरानी परम्परा और बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के फ़ैसले का क्या होगा ? जब बिल और मोशन सदन में एक-साथ चर्चित हैं, तो उन पर टुकड़ों में वोट कैसे ले सकते हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not presuming that because of the majority this is bound to be lost. I have to look at it objectively. What you are imaging is not ging to happen. In case Mr. Fernandes' motion is carried th debate on this is adjourned and the debate on his motion continues, and in case that motion is rejected by the House—of course, both are negative—nothing is before the House, and in case it is accepted, whatever are the consequences the House will face. This is the position. Now I shall put it to the vote of the House.... *(Interruption)*.

SHRI R. D. BHANDARE rose—

MR. DEPUTY-SPEAKER: In the process of voting, I should not be disturbed . . .

SHRI R. D. BHANDARE: You are allowing the others to argue....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I allowed him because there was some confusion.

SHRI R. D. BHANDARE: Would you like to divide the Joint motion into two parts? *(Interruptions)*.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Mr. Fernandes' motion to the vote of the House.

The question is:

"That the Debate on the Indian Railways (Amendment) Bill 1968, be adjourned." (5)

The Lok Sabha divided:

Division No. II) 15.07 hrs.

AYES

Adichan, Shri P. C.
Banerjee, Shri S. M.
Behera, Shri Baidhar
Biswas, Shri J. M.
Fernandes, Shri George
Haldar, Shri K.
Kalita, Shri Dhireswar
Kundu, Shri S.
Meghachandra, Shri M.
Mohammad Ismail, Shri
Mukerjee, Shri H. N.
Patil, Shri N. R.
Satya Narain Singh, Shri
Sen, Shri Deven
Sreedharan, Shri A.
Subravelu, Shri

NOES

Agadi, Shri S. A.
Arumugam, Shri R. S.
Awadesh Chandra Singh, Shri
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Bhakt Darshan, Shri
Bhandare, Shri R. D.
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chaturvedi Shri R. L.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Desai, Shri Morarji
Dixit, Shri G. C.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Gandhi, Shrimati Indira
Ganpat Sahai, Shri
Gautam, Shri C. D.
Ghosh Shri Parimal
Jadhav, Shri V. N.
Jagijiwan Ram, Shri
Kamble, Shri
Kasture, Shri A. S.
Kesri, Shri Sitaram
Kripalani, Shrimati Sucheta
Kureel, Shri B. N.
Laskar, Shri N. R.
Maharaj Singh, Shri
Mahida, Shri Narendra Singh
Mehta, Shri Asoka
Minimata Agam Das Guru, Shrimati
Mishra, Shri G. S.
Mrityunjav Prasad, Shri
Pahadia, Shri Jagannath
Pandey, Shri K. N.
Pandey, Shri Vishwa Nath
Pant, Shri K. C.
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri N. N.
Patil, Shri Deorao
Pramanik, Shri J. N.
Quresh, Shri Mohd. Shafi
Radhabai, Shrimati B.
Raj Deo Singh, Shri
Raju, Shri D. B.
Raju, Dr. D. S.
Ram Dhan, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Rana Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri Thirumala
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Sambasivam, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sapre, Shrimati Tara
Sarma, Shri A. T.
Sen, Shri Dwaipayan
Shambhu Nath, Shri
Sharma, Shri M. R.
Sharma, Shri Naval Kishore
Sheo Narain, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinkre, Shri
Shiv Chandika Prasad, Shri
Siddayya, Shri
Siddheshwar Prasad, Shri
Singh, Shri D. N.
Supakar, Shri Sradhakar
Uikey, Shri M. G.
Verma, Shri Prem Chand
Virbhadra Singh, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result* of the division is: Ayes: 16, Noes: 77.

The motion was negatived.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir I have an amendment, amendment No. 6.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right....

SHRI DATTARAYA KUNTE *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Kunte, I have alereadv ruled it out.

श्री जार्ज फरनेन्डीज: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन नम्बर 6 पेश करता हूं, जिस में यह प्रस्ताव किया गया है कि इंडियन

*The following Members also recorded their votes:—

AYES: Shri Yashwant Singh Kush-wah.

NOES: Sarvashri Gajraj Singh Rao, Sadhu Ram, Shrimati Savitri Shyam and Shrimati Sudha V. Reddy

रेलवेज (अमेंडमेंट) बिल के सांविधानिक पहलुओं और इस कानून को बनाने के सम्बन्ध में इस सदन के अधिकार के विषय पर अपनी राय देने के लिए एटार्नी-जेनेरल को इस सदन के सामने अपना बयान देने के लिए बुलाया जाये।" (6).

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is..

SHRI S. KUNDU: Sir, I would also like to move my amendment No. 29.

MR. DEPUTY SPEAKER: They are similar. They are barred. Yours is banned. There is another by Shri Digvijai Nath. There are two more. Only one could be moved.

Now, the question is :

"That this House aresolves that Attorney General of India be invited to address the House on the constitutional aspects of the Indian Railways (Amendment) Bill, 1968 and on the legislative competence of the House to enact the law under consideration." (6).

Let the lobbies be cleared.

The Lok Sabha divided:

Division No. 12] AYES [15.11 hrs.

Adichan, Shri P. C.	Kundu, Shri S.	Satya Narain Singh, Shri
Banerjee, Shri S. M.	Kushwah, Shri Y. S.	Sen, Shri Deven
Biswas, Shri J. M.	Meghachandra, Shri M.	Sreedharan, Shri A.
Fernandes, Shri George	Mukerjee, Shri H. N.	Subravelu, Shri
Haldar, Shri K.	Mulla, Shri A. N.	
Kalita, Shri Dhireswar	Patil, Shri N. R.	

NOES

Agadi. Shri S. A.	Ghosh, Shri Parimal	Parthasarathy., Shri
Arumugam, Shri R. S.	Jadhav, Shri V. N.	Patel, Shri N. N.
Awadesh Chandra Singh, Shri	Jagjiwan Ram, Shri	Patil, Shri Deorao
Bajpai, Shri Vidya Dhar	Kamble, Shri	Pramanik, Shri J. N.
Barua, Shri Bedabrata	Karan Singh, Dr.	Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Barua, Shri R.	Kasture, Shri A. S.	Raj Deo Singh, Shri
Bhakt Darshan, Shri	Kesri, Shri Sitaram	Rajasekharan, Shri
Bhandare, Shri R. D.	Kripalani, Shrimati Sucheta	Raju, Shri D. B.
Bohra, Shri Onkarlal	Kureel, Shri B. N.	Raju, Dr. D. S.
Chanda, Shrimati Jyotsna	Laskar, Shri N. R.	Ram Dhan, Shri
Chaturvedi, Shri R. L.	Maharaj Singh, Shri	Ram Subhag Singh, Dr.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh	Mehta, Shri Asoka	Ram Swarup, Shri
Desai, Shri Morarji	Minimata Agam Dass Guru, Shrimati	Randhir Singh, Shri
Dixit, Shri G. C.	Mishra, Shri G. S.	Rane, Shri
Dwivedi, Shri Nageshwar	Mrityunjay Prasad, Shri	Rao, Shri K. Narayana
Gajraj Singh Rao, Shri	Naidu, Shri Chengalraya	Rao, Shri Thirumala
Gandhi, Shrimati Indira	Pahadia, Shri Jagannath	Reddy, Shri M. N.
Ganpat Sahai, Shri	Pandey, Shri K. N.	Rohatgi, Shrimati Sushila
Gautam, Shri C. D.	Pandey, Shri Vishwa Nath	Roy, Shri Bishwanath
Ghosh, Shri P. K.	Pant, Shri K. C.	Sadhu Ram, Shri
	Partap Singh, Shri	Saha, Dr. S. K.
		Saigal, Shri A. S.
		Sambasivam, Shri

Sankata Prasad, Dr.
Sapre, Shrimati Tara
Sarma, Shri A. T.
Savitri Shyam, Shrimati
Sen, Shri Dwaipayan
Shambhu Nath, Shri
Sharma, Shri M. R.
Sharma, Shri Naval Kishore
Sheo Narain, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shiv Chandika Prasad, Shri
Siddayya, Shri
Siddheshwar Prasad, Shri
Singh, Shri D. N.
Supakar, Shri Sradhakar
Uikey, Shri M. G.
Verma, Shri Prem Chand
Virbhadra Singh, Shri

MR. DEPUTY SPEAKER: The result* of the division is:

Ayes: 16; *Noes*: 82.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are some other amendments also.

SHRI DEVEN SEN (Asansol): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st February, 1969.". (7)

SHRI GEORGE FERNANADES: I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th Februray, 1969.". (8)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is an amendment in the name of Shri Abdul Ghani Dar. The hon. Member is not here.

SHRI K. NARYANA RAO (Bobbili): Here, I have a point of order. Rule 74 reads thus:

'When a Bill is introduced, or on some subsequent motion, the member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:—

(i) that it be taken into consideration;.....".

So, it is only the member in charge of the Bill who can make such a motion, namely that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not correct. I have seen the rule. I have given my ruling. The hon. Member's contention is not correct.

SHRI S. KUNDU: I have a different motion; it is different from what I had given notice of . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: His amendment is the same as Shri George Fernandes's. So, it is barred.

Amendment Nos. 37. 38, 39, 40, 41 are not being moved, because the hon. Members concerned are not present here.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur): On a point of order. The Business Advisory Committee had decided that the resolution moved by Shri George Fernandes and the motion moved by Shri C. M. Poonacha should be taken up together. In spite of that, the hon. Member had moved a motion to the effect that the debate on the motion moved by Shri C. M. Poonacha be adjourned and vote was also taken thereon. Following the same logic, I now move that the debate on the resolution moved by Shri George Fernanades that this House sapproves of the Indian Railways (Amendment) Ordinance promulgated by the President on the 14th September, 1968 be adjourned . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is he moving it under rule 340?

---

*The following Members also recorded their votes:—

Noes: Shri Narendra Singh Mahida and Shrimati Sudha V. Reddy.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: No, I am moving it under the same rule under which he had moved it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No; then, he is debarred.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Let it be under rule 340.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, that is not possible. He has missed the point.

SHRI PILOO MODY: Before I say what I have to on this subject, I am glad to have learnt this very moment that you have to know all the rules by heart and to be able to quote them at the Chair's will, but if you miss your opportunity, you cannot move a Motion—at least that is what we have learnt. We learnt on a previous occasion that if the Bill is right and favourable to some it can be moved beyond the time of the clock . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not correct.

SHRI PILOO MODY: Please note my words—beyond the time of the clock.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have ruled that we were within time.

SHRI S. KUNDU: On a point of order. I think my hon. friend has risen to speak on the Bill itself. But you had already given me an assurance to allow me to raise my point of order on the constitutionality of the Bill before it is taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will call him.

SHRI S. KUNDU: But unless this is first disposed of, you cannot proceed with the Bill, according to your ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: At the introduction stage, certain considerations were given.

SHRI S. KUNDU: The Bill is how being taken up for consideration. A point of order was raised on its constitutionality. That has to be disposed of first.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That point was raised.

SHRI S. KUNDU: But I never spoke on the point. Just give me five minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes.

SHRI PILOO MODY: I am glad, this is the third thing I have learnt about procedure.

MR. DEPUTY-SPEAKER: One point I want to make quite clear. Along with his other arguments as to why this Bill should not be taken up for consideration, he can certainly make a plea that it is *ultra vires* on some points. I have already ruled that ultimately constitutionality has to be decided by the Supreme Court.

SHRI S. KUNDU: But if I can convince you that *prima facie* this Bill is completely unconstitutional out and out and should be thrown out and should not be discussed, I should be heard.

I will draw your attention to fundamental right in art. 19(1)(c).

SHRI PILOO MODY: No member of the PSP should be allowed to quote the chapter on fundamental rights.

SHRI S. KUNDU: It says—all citizens shall have the right to form associations or unions.

श्री प्रेम चन्द्र वर्मा (हमीरपुर) : यह किस रूल में बोल रहे हैं ? आप ने जब एक चीज का फैसला दे दिया तो फिर यह कैसे बोल रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: When the Bill was introduced, we were aware that the House was competent. But

[M. Deputy Speaker]

is a new stage and he has raised a point of order on the constitutional validity. To that extent, he can make a submission.

SHRI S. KUNDU: Under this right, no association, no union no trade union can be banned by law. Under this article, associations and unions are functioning. But look at the Bill. They have never anywhere mentioned about strike. But they have brought in this Bill in such a way that strike would be prohibited out and out. See the notification issued on 14th September, 1968. They have stated clearly in the shecond paragraph.

SHRI RANDHIR SINGH: What is this, all sorts of irrelevant things being said? Do not allow time to be killed like this. You have overruled him already. Do not give him too much latitude and liberty.

SHRI S. KUNDU: When real things are coming out, they are getting perturbed.

In the statement laid on the Table of the House by the hon. Minister he says clearly in the second paragraph:

> "In the context of the strike which was threatened on 19th September, 1968 my certain organisations of Central Government employees including railway employees, large scale action as mentioned above was apprehended."

So, it is pre-meditated. This Ordinance was brought becaus there was to be a strike on the 19th September, and the Bill has now followed it. Therefore, my contention is that whatever has been mentioned in this Bill is completely meant to prohibit a strike, which they cannot do under article 19(1)(c). If they mention here that they are going to prohibit strikes, it will be *ultra vires* of the constitution and so they are not doing it. Therefore, this is a black, colourable piece of legislation which they try to introduce in a different garb to ban strikes for all time to come.

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur): Let him read article 19(3).

SHRI S. KUNDU: 100B says that squatting picketing on rail track and such other things are all connected with the strike, and 100A says:

> "and he abandons his duty before reaching such-station or place without authority."

It is the right of the trade union worker to abandon the work when on a strike after due notice has been given. They do not use the word "strike", but everything that goes with the banning of a strike is in the body of the Bill. Therefore, I would fervently urge you to declare this Bill to be out of order, *prima facie* unconstitutional, and therefore it cannot be taken up for consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has referred to the right of forming associations or unions, but as he himself has read out, the Statement of Objects and Reasons says there is reasonable apprehension.

Secondly, neither in the Directive Principles nor in the fundamental rights in the right to strike or abandon work given in this Constitution. Whether it is legal or illegal, it is for the Government to decide, it is not for me. So, at this stage the point of order is not valid.

SHRI PILOO MODY: I am glad that finally a fundamental point has been established that when big people get up to speak, small people must sit down!

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not know if you are big because of your physical size or your name!

SHRI PILOO MODY: I do not think enlightening the Speaker is part of my job!

The Bill before us today is a mixed bag of tricks. In the last 20 years, since independence, we have had a system of government by ordinance, and protest by strike and the only people who have suffered have been the millions of people in this country who are what one considers as consumers.

Talking about strikes, I must admit that I am not very enamoured of strikes, because it impedes production, and therefore retards progress, but I do not think anybody in his right mind can possibly say that strikes are not a legitimate instrument of good trade unionism and of good collective bargaining to be used for a very specific purpose, to be used when reasoning has ended and when positions have hardened and justice is denied. That is the point of which strikes become a vital instrument of any society.

It is the inherent right of labour to strike. However, rights carry certain obligations and duties. Unfortunately in our country, and this I must say with some degree of sorrow, the entire trade union movement has been vitiated with politics and politicians who more often than not have used the trade union movement to further their political ambitions instead of furthering the welfare of labour.

Ultimately, no matter you can say,—you can say it till you are blue in the face—ultimately, wages have to be linked with work and productivity and bonus with profits. Nobody can get any more out of life than he is prepared to put into it.

I also believe that there are certain essential sectors of the country which demand that in those sensitive areas, certain restraints have to be exercised. I believe that there are certain spheres like the Railways, perhaps the airlines, certainly the army and police, certain vital sectors of the Government services which cannot be allowed to go on strike, where work must not stop.

Mr. Fernandes has said about the French Railway, the German railway and the Dutch railway and the Goanese Railways have gone on strike. The fact of the matter is that there are certain life-lines of the nation that have to be kept fluid at all times. When you make laws for such vital sectors of the workers where you prohibit them from the right to strike, you have to compensate them. You compensate them with procedures which permit them to get speedy redress of their grievances by impartial authorities who can give their verdict and arbitrate, and arbitrate in a manner which is binding on both the parties to the dispute. It is not only good sense, it is good labour relations, it is a good basis for a civilised society.

Even now when this Bill has been brought forward, what does this do? I tried to read through the Bill and make sense out of it. Mr. Fernandes is extremely worried about it. What is in the Bill? I find Section 71(b), 47, 121, 126 and particularly 128, 129, 131, 137 and 148 are rules of the Railway administration which already empower the Government to do what they please with the railway employees.

Yet, I find another Bill has been brought forward, only for one specific purpose, to get rid of the ordinance which has to be replaced. It has to be replaced with another innocuous, Bill. This Bill arms the Government with powers which they do not need, powers that it can never use, powers it does not have the capacity or competence to use. This has been the history of this Government for a long time, yet they go on arming themselves with powers week after week, month after month, year after year, which they have never been able to use with any degree of force or rationality.

What happened? A strike was threatened. Government knew about it. Parliament was in session. They did nothing. They go and pass an ordinance. This is not something new. They have been doing it for a long time and it is typical of the way they

[Shri Piloo Mody]

operate. For issuing an ordinance you do not have to argue with Mr. Fernandes. They pass an ordinance. It is only later that there is a *jhagda* over here, knowing that the votes that they have in this House help them over whatever inconvienience they have, the Minister of Parliamentary Affairs bearing the principal brunt.

No legislation has been introduced, even now, in the provisions of this Bill, to protect those sections of the people from whom you wish to take away the right to strike. You have not compensated them in any fashion whatsoever. I know that there is certain machinery like the JCM and other paraphernalia and adjudication, arbitration and so on. I hear a lot about them. All I know after hearing all sides is that no dispute ever gets settled by those procedures and certainly not in time—time being the essence.

I know demands have been pending with the railways from the workers for years and years, but still, not dealt with by all the machinery that they claim they have. Therefore, I find that it taxes the credulity of a person when they say that they have these remedies. Somehow they just do not get used.

What does this ordinance say? Nothing. Therefore, I suggest that if you want to bring forward rational legislation in the place of this Bill, do so in a manner where you specifically state that for a certain particular section of the railway, not all, everybody in the railway is that indispensable—this could be applied. The railway, as my friend says, employs 18 lakhs of people including regulars and non-regulars, and not all of them are essential. Restrict your Act to those who are essential like the railway engine-driver or the guard or the signalman who make it possible for you to run the railways even though the rest of them go on strike. Because, after all, remember one thing: that if the Railway Board for instance went on strike nobody would know that the railways have suffered in anyway, just as Acharya Kripalani said, when the Uttar Pradesh Government servants were on strike for three months, nobody was aware of the fact because they do no work. Similarly, you must distinguish between essential and non-essential workers in the legislation. When depriving essential workers from the right to strike, they must create a very special machinery to see that their grievances are adjusted, and which would be binding on both the parties, and not permit the Government, which is in the habit of saying that "it is our decision, whether we accept the recommendations or not", to escape.

For good or bad, I agree that these people have condemned the ordinance. I think it was a black ordinance. Although it was meant to serve a good purpose, it was a black ordinance.

AN HON. MEMBER: Like your coat.

SHRI PILOO MODY: But what time the ordinance was there, it was the law of the land and this, above all. I want to emphasise: that the law of the land must be observed and to that extent, I was against the strike that took place. It was their duty, the duty of my hon. friends who are here, who have been instigating these workers to go on strike, to tell the workers to observe the law of the land. (*Interruption*) I maintain that if an ordinance is passed, it becomes the law of the land and it becomes the duty of every citizen, therefore, to persuade other citizens to see that the law is observed. If it is a bad law, there are places where bad laws are fought, such as this forum, the place where we are standing, because ultimately we want to create a society where law and order will prevail and where social justice must be done.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Bill though

I must say it does not give me much pleasure to support this Bill. I have been long associated with labour. I sympathise with labour and I have worked for them. But the time has now come when we have to think of the safety of the society. Very eloquently it was asked by our friend Shri Fernandes that why was it necessary for the Government to do this, that and the other, and why did the Government take punitive action against their employees. The Government by these actions blackened their face and got a bad name. I am putting a very simple question: why was it so necesseary to have the strike, even the token strike on the 19th September? What was the urgent necesseity for it? It was, if my hon. friends would not start shouting, the mid-term poll in West Bengal, which was looming large before them, the opposition parties.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI: Even the government servants were divided. Some wanted an indefinite strike, some a token strike. Some did not want to go on a strike when Parliament was not in session, because that is their biggest forum. But it was necessary. They could not wait because the election was coming.

15.35 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair.*]

Why was Government compelled to take action even when it was a token strike? It was because of the postures adopted by the railwaymen, the resolutions they passed that "we would abandon the trains in the middle; we will work to rule" etc. I know how people suffer whenever work to rule is followed in this fashion in the railways. If a driver or guard works over-time and if relief does not reach in time, there are rules and regulations to compensate him: We can by all means go into the question of improving those rules. But here we are dealing with deliberate abandonment of the train. They had declared that they were going to do it. That fact has to be taken cognizance of. I would say that those who advised the workers to adopt such methods were not friends of the labour. What is the philosophy behind a strike? The very basis of a strike is firstly, that the strike.s' cause is just and that they take upon themselves suffering which evoke the sympathy of the public. Public sympathy is the sanction behind the working of organised labour. Where the labour work in such a manner that they lose the sympathy of the public, then those who give them such advice are working against the interests of labour. That is why I have risen to say a few words in support of this Bill. Otherwise, it is not palatable to me to speak on a measure where we are endeavouring to curtail the rights of labour.

These hon. friends of mine here who thought they were serving the cause of labour were doing immense disservice to labour. The labour knows it. One day before the 19th, I happened to meet certain Trade Union leaders; they said, "We are sorry." We have been involved in it. We do not know how to get out of it. The right and left communists have brought about this situation. They are challenging us. If we go back now, we will be vilified by rival labour leaders. We want unity among the labour. That is why we are joining the strike. Don't ask us more about it". Under such situation, the Government was compelled to pass this ordinance.

This is a small Bill which seeks to replace the ordinance. There are only two clauses in it seeking to add two more new sections—100A and 100B. Mr. Piloo Mody rightly asked, why do you want these extraordinary powers when all these provisions are already there? The Indian Railways Act provides for 'wrecking' or 'attempting to wreck' a train or 'endangering the safety of the passengers'. It does not provide for the 'abandonment' or obstruction of a train in the manner it is now being done. There is reason for it. The original Act was passed in 1890 when the present features of

[Shrimati Sucheta Kripalani]

labour movement did not exist. Only in recent years we have seen these tactics as gheraos, abandonment and obstruction of trains, etc. If a driver gets physically tired, for that provision is there in the Railway Act. But because these new tactics have come in, endangering the safety of the public and causing inconvenience to them deliberately, to take care of such deliberate abandonment of duty, this Bill has been brought.

It has been said that Gandhiji gave us this weapon of obstruction or *Satyagraha*. But Gandhiji gave the weapon of obstruction by non-violent methods. Now what is the position? Out of such situations, violence arises. We have seen what is the present-day tendency? Disorder, violence—lawlessness everywhere. Let us see the situation prevailing among students. We are perhaps ourselves responsible for this indiscipline. I do not want to absolve ourselves from the blame. What is however the present situation? There is so much of violence in the atmosphere that it is becoming a matter of deep concern to all of us. How to check this trend? This morning we discussed the affair of Delhi students resulting in the burning of the buses and pushing them down! Here I have got a newspaper cutting. I do not want to take too much of the time of the House by reading it. This is a report from *The Hindu*. This is about Kerala, not governed by a reactionary Congress Government. This is about the reprot of the one-man Commission set up to enquire into some troubles in the Kodumon and Chandanappally estates of Kerala. The finding was that it was very unjustified and that it was organised by the Marxist Trade Union. The report says that "there were violent demonstrations, disruption of communications by digging trenches and cutting off of telephone connections, looting of rubber products and other valuable materials" and so on. "The Commission said that it was clear that the gheraos were organised by the Marxist workers and their sympathisers from outside. It has held that these gheraos came substantially within the definition.....and so on. Every day we are getting reports of this kind of lawlessness. Suppose the train is abandoned at night, in a forest area. There are sick people in it; there are women travelling alone; there are children. Who will give them food and water? Their life and safety is endangered. Whom are you going to punish by the strike? The people? The strike is against whom? Against the passengers and against the people? Somebody's parents may be waiting at the destination to receive their sick child? You want to leave the passengers in such a manner? Railway is an essential service; it is a public utility service. Railway workers have got more responsibility than others. Their actions are against the society, therefore, Government is very much within their rights to pass this Bill.

I will quote some figures in reply to the claims of Shri Fernandes. The High Powered Committee on Security and Policing on the Railways (of which Shri Shantilal Shah, a very honourable Member of this House is the Chairman) has given a report. During the last 10 months, railways were held up over language agitation, tuition fee agitation by students and various other such agitations including some labour troubles. The number of such cases of hold-ups were 670 in West Bengal, 243 in Andhra Pradesh, 401 in Madras and 142 in Uttar Pradesh. The number of cases of obstruction of trains either on account of language agitation or any other agitation was 243 in Andhra Pradesh, 401 in Madras, 142 in U.P., 5 in Bihar and 2 in Mysore.

SHRI DHIRESHWAR KALITA: What about major railway accidents? Please quote those figures also.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI: I will come to that. In the present situation of lawlessness and violence it is enjoined upon the Government to

serve the public and ensure their safety. Therefore, I support this Bill.

Certain constitutional points were raised earlier. One is that this violates Art. 14 dealing with Fundamental Rights. In this Act, certain offenders are categorised and offences are listed. Such listing is there in all our labour legislations and it was never held that they offended against Art. 14 of the Constitution. Therefore, this argument has no validity.

Similarly, some other hon. Members quoted article 19 and asserted that the present Bill offended against it. That article says in Sec. 19(3) that:—

> "Nothing in sub-clause (3) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause."

So, that argument that it offends against Article 19 has also no basis. Though various other arguments have been given, I do not wish to go into them because they have no substance.

I do not like such a Bill but, taking the entirety of the situation into consideration, I support it. At the same time, I would like to draw the attention of the Railway Minister to some points, which were referred to by some of my hon. friends. What is the performance of the railways? We are very sad and concerned at the things that are happening. For the last few months one accident after another has occurred. We would like to know whether the failure is at the administrative, human or technical level. At whatever level it is, it has to be rectified. If it is at the human level, we have to see whether there is any element of sabotage. If it is at the administrative level, then the Railway Board has to own responsibility. The Board consists of experts who are experienced people. If things are going wrong at their level, they have to own it and not hold up their hands and say "after all, accidents do happen". Then, if the accident takes place because of the indifference of the workmen, we should not slur over it either. We have to go into the entire question, and set things right.

Coming to trade unions, it is not their duty only to fight for the rights of the workers. Certainly, that is their first responsibility. But, at the same time, it is also the duty of the trade unions to see that the workers give better performance and they are proud of their own performance. In a country which is developing all of us have to pull our weight together to see that our country progresses. If we fight amongst ourselves and if we work in this slip-shod manner we cannot progress.

One word more and I have finished. After the strike of the 19th September, this Bill has come. In fact, it is the result of the strike and the trouble that occurred during those days. The situation is no doubt a difficult and delicate one. I would appeal to the railway authorities as well as to the workers to close this unhappy chapter. Let there be no estrangement or ill-will among them. The sooner it is over the better it will be for all concerned. I know the feelings of the workers. A lot of them have come to me repeatedly and said that they are sorry for having been misled into taking part in the strike.

SHRI GEORGE FERNANDES: Nonsense.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI: There is no point in getting agitated and repudiating the truth. I also know the workers. There should be better relationship, better rapport between the workers and the authorities. How you have to achieve it, it is for you to decide.

Then I come to the point which Shri Piloo Mody also raised. We do not want to give some categories of workers as in essential services too much of liberty in the matter of

[Shrimati Sucheta Kripalani]

strikes. That is understandable. But, then, when we seek to restrict their freedom in the matter of strikes, we have to see that the negotiating machinery functions properly and its decisions are speedily implemented. For instance, if there is any point of disagreement in the Permanent Negotiating Machinery, it should be referred to arbitration. I want to know from the railway authorities now many such cases have been referred to arbitration since 1956. If that machinery does not function properly and there is discontent in the minds of the workers, a time comes when they take law into their own hands and then you come out with a harsh legislation. We do not want harsh legislation; neither do we want the workers to take law into their own hands. Therefore, grievances settling machinery should function in such a way that the grievances of the workers are settled expeditiously.

Often promises are made but even then things are not set right. I know, there are hundreds of cases relating to salary etc. which are pending for the last four or five years. Cases like salary of a man who officiated in a higher post, unpaid wages, allowances, TA, Overtime, etc. Why can they not be put right? Why can a special body not be set up to clear all the arrears so that at least one legitimate point of grievance is removed?

Recently the Home Minister announced the withdrawal of termination notices from 44,000 temporary employees. I would like to know whether you have tried to find out actually in how many cases those notices have been withdrawn? I am told that the local authorities are not withdrawing them and are not reinstating them. They are out to vent petty revenge on the workers and it is vitiating the atmosphere.

Then, certain things are thoughtlessly done. In a place like Pandu in Assam, which is a huge railway area, 2,000 yards around the administrative building has been declared as protected area. Within that area they have workers residential accommodation. Untol hardship is being felt by the people due to this. If I am wrong, you please correct me.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): Not wrong; you are correct.

AN HON. MEMBER: It is the State Government.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI: Even if it is the State Government, it must be put right.

Then, I am told about similar situation in Izatnagar in UP. As far as Assam railway workers are concerned, in that dangerous Naga area when every day railway trains were being blown up, railwaymen worked and showed their loyalty and courage. If you give them confidence, you will get loyal service from them. Why has this been done in Pandu? If it is a source of irritation to the workers, it must be removed. I am deliberately making out these few points on behalf of the workers.

I want to make a last plea. There are two demands which to my mind are reasonable. You have after the strike dismissed the temporary employees and suspended the permanent employees. Why not suspend the temporary employees also and inquire into their cases? Secondly, many innocent people were arrested or came under penal action though they were just passers-by. Why not carefully scrutinise these cases so that nobody feels that injustice has been done?

While I support the Bill, I also plead with you to temper justice with mercy and redress all the just grievances of the workers.

SHRI J. M. BISWAS (Bankura): Mr. Chairman, after hearing the hon. Member, Shrimati Sucheta Kripalani, at least I have come to one conclusion that sometimes to deal with a subject

of which someone is not aware is a very dangerous work. She started by saying that she was connected with some labour organisation, that she knew labour problem very well and she ventured to speak about railway labour. She tried to speak about some of the railway problems also. I think, she might know many things in this world but she has no idea about the railway workers and their problems.

So far as this Bill is concerned, I would like to say a little elaborately what Shri Piloo Mody has said in one word. I am reading only a few lines of section 128 of the Indian Railways Act, 1890. This section says:—

> "If a person, by any unlawful act or by any wilful omission or neglect, endangers or causes to be endangered the safety of any person travelling or being upon any railway, or obstructs or causes to be obstructed or attempts to obstruct any rolling stock upon any railway he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years".

So, the rule is there. Shrimati Kripalani says that there might be a rule about certain other offences but there is no rule about obstruction. The hon. lady Member did not care to read section 128 of the Indian Railways Act which has also preventive measures against obstructions.

Not only this, regarding the hours of duty of railway workers, the adjudicator's award says that a member of the running staff will normally be required to do duty for eight hours but in case of an emergency they may be required to perform more hours of duty that is, up to 10 hours, after which they can demand for relief. Now, according to the same Award the duty hours should be counted from wheel-moving. The railway administration invented a flaw there. They say that the wheel movements should be counted from the time when the train starts from the station. But, actually, the driver of a steam engine is required to appear for duty about two hours before the time the train is ordered to move. Similarly, the guard appears for duty much before the time the train is ordered to move. If the train starts 3 or 4 or 5 or even 10 hours late, although the driver will have to remain on duty in the engine and the guard also will have to be on duty yet their duty will not be counted for demanding relief.

From the side of the All-India Railwaymen's Federation and from the side of the Railwaymen's Union, we also demanded, "If you want to count the duty hours from the departure of a train—the train means, according to general rules, an engine or any other self-propelled vehicle within the track—then why don't you count the duty time from the time an engine comes from the loco shed?" They refused to agree to that suggestion. I know many Members will speak on the subject. But the unfortunate thing is that those things are not known to this House. Those chapters of railwaymen's life are in the dark. I can show you from the records where after 13 or 14 or 15 hours continuous duty, in the summer season, in the steam engine tired of remaining in terrible heat the driver has asked for relief or if a driver has stabled the train not getting the relief it is not that he has deserted his duty he has been punished. He says: "I have been working for the whole night. I have completed 15 hours duty. I want relief." But according to the administration that is a severe offence on his part. I can show thousands of cases where running staff after 12 hours duty for stabling trains were put under suspensions and their increments were stopped.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Now they will be jailed.

SHRI J. M. BISWAS: Now, this amendment gives them the power to put them in jail, as my hon. friend, Shri Dhireswar Kalita rightly pointed

[Shri J. M. Biswas]

out. They are not happy by placing them under suspensions; they are not happy by stopping their increments; they are not happy by taking other penal measures.

There are the Establishment codes and there are the service conduct rules. What Shri George Fernandes mentioned, even the Railway Minister does not know. If a relation of the railwayman, if the wife of the railwayman, is supporting a political party or becomes member of a political party according to the service conduct rules, the railwayman, like a C.I.D., will have to bring the matter to the notice of the railway administration. Such a system is there in the Railways. There is nobody to look after that.

16 hrs.

After the railway accident, we sometimes find tears in the eyes of the Minister. I want to know from them, through you, Sir, whether those tears are crocodile tears because they themselves, by this time, have also come to know what are the real causes of the accidents. I can show you the type of cases where the running staff even after 24 hours duty at a stretch, were not given relief. Now, according to the existing rules, after 10 hours duty, he can demand relief and stable the train if the relief is not available on completion of 12 hours duty. He is punished although according to the rules, on completion of 10 hours duty he can demand relief. According to the rules, he is authorised, he has been given the authority, to ask for relief on completion of 10 hours of duty and on completion of 12 hours of duty if the relief is not available, he is authorised to stable the train. But even for having stabled the train according to that rule, they have been punished as I mentioned. Now, after this amendment, even after completion of 12 or more hours of duty, he will not be permitted to stable the train. The only reply from the administration will be, "There is no relief; you will have to take the train to the destination". It does not matter to them even if the train meets with an accident, and if the driver dies, I can say in this House that his wife will not get even the little amount of money which the wives of railwaymen are otherwise entitled to get; if this amendment to the Act is accepted it will deprive the family members of Railwaymen even of this little amount. The Britishers established the railway system in this country and they ruled for so many years. It is over a hundred years since the railway system was established. The Britishers did not feel the necessity to bring such an amendment to the Act. This Congress Government has also been in power for the last 21 years. Even in the year 1960 there was a strike, and the Railway staff, under the call of the Union, under the call of the Federation, struck work in 1960. But the then Prime Minister, late Shri Pandit Jawaharlal Nehru, did not feel the necessity to make such an amendment to the Act. But now his daughter, with Mr. Poonacha, Mr. Parimal Ghosh and other corrupt bureaucrats in the set-up is feeling the necessity to bring such a dirty, undemocratic, nasty amendment (*Interruptions*). After 21 years of freedom, if there had been a rule, if there had been a law, reducing the duty hours of the running staff, we would definitely have appreciated that. But this Government, instead of enacting such laws which can give relief to the people is trying to bring this anti-people law by which they want to butcher railwaymen. This is a conspiracy by this Government to keep the Ordinance, which was an illegal child, living for ever; they want to keep the undemocratic Ordinance alive for all the years to come.

There have been strikes in other countries also. In the USA there have been strikes; in France the other day,

there was a big strike; in Italy, in England, in Japan, everywhere there have been strikes in Railways.. (*Interruptions*) in France, the workers not only struck work but also captured the industry. But even in that situation, they did not promulgate a dirty Ordinance like this. The Railway authorities in France or USA or England or Germany did not feel the necessity to take such an undemocratic action to curtail the rights of the railwaymen. To strike work is a legal right. There was a strike in 1960 in this country also. When Government heard of this 19th September strike, they got nervous and they perhaps thought that after the promulgation of two special Ordinances in the Railways, the workers, out of fear, would not participate in the strike. But the unfortunate position for them is that ten lakhs of Central Government employees, facing such an ordinance, participated in the strike.

Sir, after the strike what has this Government done? I would like to mention here, with your permission, about one incident at the station Kalka in Northern Railway. I had been to Kalka Station the other day. I will give you a few instances where the police broke open the door of the railway men and entered their houses. Here is a joint petition signed by about 600 Railwaymen which has been sent to Shrimati Indira Gandhi, Prime Minister of India. I am quoting from this Joint petition and I am going to place it on the Table of the House. In this joint petition, there is one case of Shri Prem Prakash. His quarter No. is 255-H. The police broke the door open and entered the quarter. His mother and his wife were severely beaten up and made naked. There is another case of Shri Lakshman Ram, quarter No. 246-A. The door of the quarter was broken; the Police entered the quarter and had beaten the inmates severely while they were engaged in cooking their food. In another quarter of Shri Ram Dass, quarter No. 246-B, the door was broken and he and his wife were beaten up severely. Sir, in one quarter, it is very interesting to note that they found nobody. They found one buffalo. They beat the buffalo severely. In another quarter, they beat a dog. From their attitude it appeared that the police were adamant to beat whomsoever they came across. In a station like Anara and Adra in the S. E. Railway, what did they do? Sir, the wives and children of railwaymen came out in a procession, a procession of 5,000 people, to rejoice the victory of the success of the strike on the 19th September at Adra. But what did the police do? The Police made brutal teargassing and lathi-charge. 48 people were injured in Adra alone. Five ladies were injured. One lady, Shrimati Sudhanshu Bala Bhattacharjee the eldest sister of a travelling ticket examiner was severely beaten up. There were three fractures on her hands. Her hands are still under plaster. There is another railway employee by name Amaresh Chatterjee, Guard, Anara. He sustained head injury resulting in 18 stitches in his head, Sir. This is the behaviour of the police towards innocent people in this strike of 19th September. After all, Sir, what was the reason? What was it that they demanded? According to the agreement, you have to set up a joint consultative machinery. If there was disagreement between the labour and the administration in the Joint consultative machinery on any issue that matter will be referred to arbitration. That was the agreed formula. And when the question of merger of D.A. with basic pay, full neutralisation of the rise in the cost of living index, and the demand for need-based minimum wage came up, and these were not agreed to; hence the labour leaders demanded that this issue should be referred to the arbitration. And that was the only thing. But this Government not only failed to refer the issue to arbitration but also gave it a political colour, as mentioned by Shrimati Suchets Kripalani and that

[Shri J. M. Biswas]

is how it came when this Parliament was not in session this ordinance was promulgated, like an illegal child taking its birth. All these things took place. I say that they have got thousand and one rules to cripple the railway employees. I have talked with some railway officers. They also started laughing after hearing about these amendments. What is the good of making another enactment when we have so many rules and regulations already which can easily be employed against the railway employees in case of any lapse.

What is the need of making more laws and more enactments? I would request the Ministry of Railways through you to consider that this is a superfluous Bill because all these provisions are there in the Indian Railways Act; all the provisions are there in the General Rules, in the Railway Establishment Code and Service conduct Rules. This legislation is, therefore, superfluous and unnecessary. It only shows after the last general election that the Congress Party, have been isolated from the people and after seeing the successful strike of 19th September, they are afraid of the workers, they know that the workers are not with them, and out of fear and with the desire to retain their power in the country, they have tried to take help of the police, lathi and all these antipeople, antiworking class laws.

Shrimati Sucheta Kripalani has said that the public does not support the 19th September strike. Agreed—let this legislation be circulated for public opinion. I throw this challenge that if majority of the people supports this bad law I will bow down my head to this Government and go out of this Parliament and never come back here. Let Shri Poonacha accept the challenge and do the same. Let Shrimati Kripalani stand up and say that she is prepared to accept my challenge.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Tarkeshwari Sinha: A large number of members want to speak. If Members will be brief and avoid repetitions, I will be able to accommodate many hon. Members.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh): I will take only 10 minutes. I am glad that the hon. Member who preceded me said while summing up his speech that there are many rules and regulations which are quite enough to take te entire situation in hand. That means the hon. Member has already agreed that the laws restraining railway employees for violating basic proprieties and for trying to sabotage railway property are there in other legal privisions. Therefore, the contention of the hon. Member who has moved the Resolution does not stand.

SHRI J. M. BISWAS: This law was enacted by the Britishers in 1890.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: The hon. Member had the unique prerogative of getting 35 minutes, but he wants to deny me even 10 minutes.

According to the hon. Member, the Railways have got the authority under the Indian Railways Act, (9 of 1890) in which all punishable offences under the Act have been legislated. These present provisions are only adding to some of the provisions which have already been made. Neither 100A nor 100B therefore violates article 14 or 19. Article 19 (1) (b) gives the right to assemble peaceably and without arms, but article 19(3) provides:

> "Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the State from making any law imposing, in the interests of public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause."

Let me give an example. If a railway servant wants to paralyse the running of train, or members of the public start squatting or picketing on the railway track, is it not proper that they should be brought to book under the law since it is in the interest of the public. Public interest is not only the interest of the employees? Therefore, if the interests of the public are affected, if they are put to inconvenience, Government can put adequate restrictions by law, and therefore it does not violate article 19.

SHRI S. M. BANERJEE: Now there is no need of calling the Attorney General.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: I am very glad that the hon. member appears sometimes very reasonable person. Whenever I get up to speak I am sure I can convince him. I am glad the hon. member seems to be satisfied and does not now demand the calling of the Attorney General. I am grateful to the hon. member for his observations.

Shri Biswas quoted certain rules, but I would like to mention that section 131 of the Indian Railways Act already contains a provision authorising railway servants as well as officers to arrest without warrant, persons guilty of certain offences under the Railways Act. The new sections 100A and 100B only seek to amend that provision to include some more offences which are going to be brought under the law. Therefore, the contention that article 21 is violated by this provision of the Bill also does not hold good.

Apart from the above, section 59 of the Criminal Procedure Code gives this freedom to any civilian person to arrest another person if, according to his view, he commits a non-bailable or cognizable offence. If that power is available to the ordinary citizen of the country, it is very much available to the Railway Department.

Apart from it whose interests are we talking about? I can understand trade union interests being preserved. I know that Mr. George Fernandes is a very important trade union leader in Bombay, but does it mean that he does not allow the factories to run? He does! Most of the industrialists are his friends—not that they exploit them,—but in any working arrangement between the employer and employee, a certain understanding can be reached, a satisfactory understanding is a possibility. Mr. George Fernandes himself is a trade union leader. Therefore, I do not understand why the trade union activities should always be brought into the purview of the political manipulations. Therefore, while sympathising with lots of demands which have been made in this House in regard to trade unions—I have also worked a little bit in the trade union movement, I know the genuineness of their cause; I think George Fernandes does not believe in going into other people's history, he is only interested in his own history—I would like to submit that there is no point of difference so far as the demands are concerned. I do not have any quarrel with Mr. S. M. Banerjee or Mr. George Fernandes that some of the working conditions of the railway employees should be improved. My quarrel is this. Why are they making this as a political issue. It should not be made into a political issue.

SHRI RANDHIR SINGH: That suits them.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: By making them power in political chessboard, we are not helping their cause; we are only obstructing their cause. So far as the point raised by Mr. George Fernandes is, I agree the conditions of the railway workers must improve, but in democracy we have not been given the right of might. We have been given

[Shrnmati Tarkeshwari Sinha]

the right of negotiation and also the right of peaceful strike. Peaceful strike does not mean obstruction. You can strengthen your demand by peaceful strike. But I do not think when talking about the trade union movement in this country or in the other parts of the world, one can say that the other trade unions which are very strong trade unions like the American trade union or the British trade union ever go and provoke themselves to the extent to damage the railway property or damage the institution in which they are working. So many strikes have taken place—seamen's strike, transporters' strike and so on but not one of them indulged in burning of buses or other things. Who is going to plead the cause of the doors, windows, glasses, railway track and batteries and the like. You do not believe in pleading the cause of the inanimate. Members of Parliament should realise what an amount of damage to the railway property is caused. Nobody protests for the doors and windows. Damage to the property can go along with great indifference, with great negligence. This does not help the trade unions in spite of your right to strike, right of the trade unions, to legally or lawfully conduct their affairs. They should see that they create this obligation that the railway property is protected and is maintained by the leaders of the trade union. But I do not think Mr. George Fernandes can take give the guarantee on behalf of his fellow friends in Calcutta—His Party does not believe in that—Even other friends who are sitting by his side, can they give this guarantee. Can Mr. George Fernandes give the guarantee that they will never practice arson and looting and all these sort of troubles that are going in the country will be prevented by the good offices of Mr. George Fernandes. Trade unions and the trade union leaders have not been able to prevent this kind of harassment and this kind of obstruction to the railway property.

I would like to bring one instance to the notice of the hon. Member. On 19th September 1968 at Pathankot in the Northern Railway a mob of thousand people consisting of large number of railway employees took away the firemen of the train and prevented him from work. Is it an obligation of the trade union movement? Another instance I will give that in N.F. Railway on 19.9.68, the loco staff at Jalakdhari was assaulted and forced to leave. I would also like to mention that the Chief Engineer who has nothing to do with the arbitration of the trade union wages or the trade union rights was going back home from the office. He was assaulted and the accounts officer was also assaulted by the railway employees. Is it the obligation of the trade union movement?

Sir, like this there are hundreds of examples of the railway employees assaulting the superior officers, gheraoing their own works manager, deputy manager, and so on, and sometimes keeping them locked in a room, so much so that sometimes those officers had to run away through the backdoor. It is on account of such things that this Bill has been brought forward. The large-scale destruction of the railway property in which the railwaymen, and sometimes the railway drivers connive because of the bad influences they are subjected to and the wrong type of leadership. Now, I should like to refer to your own State . . .

MR. CHAIRMAN: You must conclude now.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: I am coming to the last point. I am going to refer to your own State, Andhra Pradesh, and then to Bihar, West Bengal and a few other States. The loss to railway property due to agitations was Rs. 23,55,000 in Andhra. Owing to the student agitation in Andhra Pradesh, the loss was Rs. 21,000. Due to anti-

Hindi agitation, the loss was Rs. 1 lakh. In Bihar, owing to the Patna student agitation, the loss in April, 1965, was Rs. 3 lakhs. In Kerala, owing to the food agitation, the loss to the railway property and damage to the railway property was Rs. 74,630. In Madras, owing to anti-Hindi agitation, the loss was Rs. 57, lakhs in 1965, and Rs. 19,82,000 in 1967. In Maharashtra it was Rs. 64,000. In Punjab, the loss in 1966 has been Rs. 66,000. In Uttar Pradesh, owing to anti-English agitation elsewhere it was anti-Hindi agitation but here it was anti-English agitation—the loss was Rs. 4,60,000 in November, 1967. In West Bengal....

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech now. Do not put any further strain on the time.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: Last but not least, in West Bengal, the loss was Rs. 65,43,000 in 1966. If these are not the causes for bringing forward a Bill like this, then what other reasons will be there to bring forward such a Bill?

But I request that mostly the Government should bring forward Bills and not ordinances. This kind of ordinance is not a healthy feature for parliamentary development. Therefore, in future, the Government should seek to bring the Bills or resolutions in a proper manner and not issue hasty ordinances.

Before I sit down, I would only like to repeat what Shri George Fernandes has said about the trade union leadership. I would like to quote him; he said that the Railwaymen for instance must be told in simple language that through one united organisation they possess the capacity to paralyse the country, and those with the strength to paralyse the country might as well take on the job of running it. If he publicly says that one can paralyse this country by a wrong direction of the trade union movement, it is not necessary and desirable for having this Bill to see that his slogan does not materialise and come true?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आधा बताया । मैंने कहा कि वह बन्द कर सकते हैं और चला सकते हैं । मैंने चलाने पर भार दिया है । मैं यह चाहता हूं कि वह चलायें ।

MR. CHAIRMAN: It is all over. She has given a major portion of her attention to your speech .

SHRI GEORGE FERNANDES: I am really flattered.

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं श्री जार्ज फरनेन्डीज के मोशन की सपोर्ट करने के लिये और पुनाचा साहब के बिल की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । लेकिन अगर बदकिस्मती से जैसा कि हाउस की तशकिल से जाहिर होता है, पुनाचा साहब का बिल पास हो गया तो रेलवे एम्प्लाईज की हालत एक शायर के लब्जों में यह होगी :

न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है ।
घुट के मर जायें यह मर्जी मेरे सैयाद की है ।

सभापति महोदय, कदम कदम पर जम्हूरियत और समाजवाद का नारा लगाने वाली और बात बात में महात्मा गांधी का नाम दोहराने वाली इस सरकार ने पार्लियामेंट के पिछले सेशन के सिर्फ 14 दिन बाद आर्डिनेंस की सूरत में यह काला कानून ला कर न सिर्फ जम्हूरियत का खून किया है, न सिर्फ सरमायादाराना जहनियत का इजहार किया है, न सिर्फ महात्मा गांधी की जन्मशताब्दी का आरम्भ कर्मचारियों के खून की होली से किया है बल्कि अपनी कमजोरी का भी सबूत दिया है । इस सरकार को पिछले सैशन में बखूबी मालूम था कि मुलाजमीन हड़ताल करने वाले हैं, लेकिन इस बिल को वह उस सेशन के दौरान नहीं ला सकी, अब इस बिल को लाई है,

[श्री सूरज भान]

अब तो इस आर्डिनेंस के पोस्टमार्टम वाली बात है ।

सभापति महोदय, रेलवे के दो लाख पैंतीस हजार मुलाजमीन ने 19 सितम्बर को हड़ताल करके इस काले कानून की धज्जियाँ उड़ाई । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये रेलवे कर्मचारी पेशेवर हड़ताली नहीं हैं, ये खानदानी हड़ताली नहीं हैं, पुनाचा साहब इस बात को जानते हैं कि ये दो लाख पैंतीस हजार कर्मचारी जिन्होंने हड़ताल की इन रेलवे यूनियनों के ओहदेदारों ने रेलवे में भरती नहीं किया था । रेलवे के जिम्मेदार अफसरों ने इन्हें रेल के महकमे में भरती किया था । यह रेलवे के सर्टिफाइड कर्मचारी हैं, जिनकी, मुलाजमत में रखते वक्त, सी० आई० डी० पुलिस के जरिये तसदीक कराई जा चुकी है, फिर सवाल यह आता है कि वे हड़ताल के लिये मजबूर क्यों हुए ? सभापति महोदय, आप बाजार में जाइये, एक दर्जी पहले एक कमीज की सिलाई एक रुपया लेता था, आज वह कहता है कि महंगाई के पेशेनजर आटा मंहगा हो गया है, मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता, इसलिये मैं कमीज की सिलाई दो रुपये लूंगा—वह ज्यादा मांग सकता है और आपको देना होगा । एक राज मकान बनाता है, पहले वह दिहाड़ी के पांच रुपये लेता था, आज वह कह सकता है कि आटा मंहगा हो गया है, मैं सात रुपये लूंगा । वह मांग सकता है और आपको देना होगा । लेकिन एक रेलवे कर्मचारी जो स्टेशन पर काम करता है, रेलवे की वर्कशाप में काम करता है एक महीने के बाद जा कर अपने अफसर के सामने यह नहीं कह सकता कि मंहगाई बढ़ गई है, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं होता है, इस महीने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाय, अगर कहेगा तो उसकी बात को सुना नहीं जायेगा । रेलवे मुलाजमीन ने जे०सी०एम० के जरिये अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार ने उनको नहीं माना । जब सरकार नहीं मानती है तो फिर मुलाजमीन के पास और क्या रास्ता रह जाता है ।

कुछ लोग कह सकते हैं कि वे देशद्रोही है, हड़ताल कर के देश का नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन देशभक्ति कुछ थोड़े आदमियों की बपौती नहीं है, उनकी देशभक्ति पर शक नहीं करना चाहिये । 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था, अफसरान घरों में छिपे बैठे थे, मंत्रिमंडल के लोग घरों में बैठे थे—ये कर्मचारी दुश्मन के आसमान पर मंडलाते हुए जहाजों के नीचे रेलवे ट्रैक पर अपनी गाड़ियों को चला रहे थे, फौजों को सामान पहुंचा रहे थे और यह सब उन्होंने अपनी जान को हथेली में डाल कर किया था, बल्कि कई रेलवे मुलाजमीन ने अपनी जानें कुर्बान कर दी । चुनांचे देश के प्रति उनकी नीयत पर शक करना ठीक नहीं है । जब सरकार उनकी बात को नहीं मानती, मंहगाई एलाउन्स बढ़ाने की बात करते हैं तो नहीं बढ़ाती है, तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो नहीं मानती है, उस वक्त मुलाजमीन क्या करें ? मजबूर हो कर हड़ताल करनी पड़ती है । लेकिन जब वह हड़ताल की बात करते हैं तो यह सरकार उनकी हड़ताल को कुचलने के लिये यह आर्डिनेन्स लाती है ।

16.34 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

सभापति महोदय, मुझे एक मीनविर जरिये से पता लगा है कि जिस वक्त 1960 में इन्डेफिनिट स्ट्राइक होने वाली थी, गवर्नमेन्ट एम्पलाइज ने नोटिस दिया था, उस वक्त इत्तिफाक से देश के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद बीमार थे । डा० राधाकृष्णन उनकी जगह आफिशियेट कर रहे थे । सरकार एक आर्डिनेन्स के मसौदे को लेकर उनके पास गई, लेकिन उन्होंने उस इन्डेफिनेट स्ट्राइक को कर्ब करने वाले उस मसौदे पर दस्तखत करने से

इन्कार कर दिया । लेकिन आज एक दिन की स्ट्राइक के लिये इस सरकार ने वही काला कानून पास कर दिया और अब उसी तलवार को, जिससे उन मुलाजमीन का गला काटा गया, जितने मुलाजमीन रेलवे के मरे हैं, उतनी किसी दूसरे डिपार्टमेन्ट में नहीं मरे हैं, अब यह परमानेन्टली अपने पास रखना चाहती है ।

इस आर्डिनेन्स में क्या है ? यह एक ऐसी घिनावनी तलवार है जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता । अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर ता० 19 को सुबह 6 बजे रेलवे की यूनियन के चार-पांच ओहदेदार स्टेशन पर आये । उनका कुसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कहा—"मजदूर इत्तिहाद जिन्दाबाद ।" इस नारे को सुनते ही वहां पर एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट रेलवे पुलिस आये उनके साथ पुलिस फौज थी उन्होंने आते ही बड़ी बेरहमी के साथ मवेशियों की तरह से उन लोगों को पीटना शुरू किया । जब मैंने पूछा कि क्या इस तरह से रेलवे मुलाजमीन को पीटा गया था—तो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं—किसी को नहीं पीटा गया । अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन का बच्चा बच्चा स्ट्राइक पर जाने के लिये तैयार था । जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं गये ? तो उन्होंने जवाब दिया—हम हड़ताल पर जा सकते थे नौकरी से हटाये जाने के लिये तैयार थे लेकिन इस तरह से दरिन्दों की मार कौन खाये इसी वजह से वे पीछे हट गये ।

16.35 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ता० 19 को सुबह 6 बजे जगाधरी रेलवे वर्कशाप में काफी मुलाजमीन आ गये और वे चाहते थे कि गाड़ी न चलायें । वहां पर एक एक्स-रेलवे एम्पलाई था जिसका नाम चेतन दास था, उसने पहले से डिक्लेअर कर दिया था कि मैं गाड़ी को चलने नहीं दूंगा, अगर चलेगी तो मेरी लाश पर चलेगी । वह प्लेटफार्म पर आ गया उसने रेलवे इंजिन के सामने खड़े हो कर कहा कि गाड़ी को रोक लो, ड्राइवर से कहा कि हड़ताल का टाइम हो गया है, गाड़ी को न चलाओ । ड्राइवर ने कहा—मैं तो चलाऊंगा । उसने दो नारे लगाये और रेलवे लाइन पर लेट गया । ड्राइवर ने पुलिस से कहा कि इस लाइन को साफ कीजिये । लेकिन पुलिस ने बजाय इसके कि उसको वहां से हटाती ड्राइवर को धमकी दी कि तुम गाड़ी को चलाओ । ड्राइवर ने मजबूर हो कर डर कर इंजिन को चलाया, इंजिन के चलते ही जब उसका आधा शरीर कट गया और उसने चीख मारी तो उसने इंजिन को रोक लिया, उसके बाद उसकी डैथ हो गई । यह बात तो मैं समझ सकता था—चूंकि वह लाइन पर लेटा था इसलिये उस पर खुदकशी का इल्जाम लगा कर मुकदमा चलाया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उसको मार दिया गया । मैंने कहा था कि उसकी जुडीशियल एन्क्वायरी हो—लेकिन जब इन्द्रप्रस्थ कांड की ही जुडीशियल एन्क्वायरी नहीं हुई तो उसकी कौन करायगा । लेकिन उसकी मैजिस्ट्रीयल एन्क्वायरी जरूर होनी चाहिये । मैं उसके बा में आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं—ये कहते हैं कि रेलवे गुड्स ट्रेन खड़ी थी, वह रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था इसलिये कट गया । वह गुड्स ट्रेन के नीचे से गुजर कर आया था—इसी को फैक्ट मान लिया जाय—अगर वह ट्रेन चल रही थी—तो लाजमी तौर पर उसको पूरा कट जाना चाहिये था । यह हकीकत नहीं है उसने ड्राइवर को गाड़ी न चलाने के लिये कहा था, नारे लगाये थे, सब कुछ किया था, ड्राइवर को उसके बारे में मालूम था कि एक आदमी नीचे लेटा हुआ है, गाड़ी चलाने से वह आदमी मर जायेगा लेकिन पुलिस ने उसको कहा था कि गाड़ी को चलाओ । वह अक्सर इंजन के चंद गज के फासले पर लाइन पर लेटा हुआ था । जूंही गाड़ी चली उसने दर्द के मारे चीख मारी, ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली । मैं यह बात साबित कर सकता हूं कि यह सरीहन कत्ल केस है, और मैं मांग करता हूं कि अगर आप जुडीशियल एन्क्वायरी नहीं करा सकते

[श्री सूरजभान]

तो कम से कम मजिस्ट्रीयल एन्क्वायरी जरूर करायें ।

इतना ही नहीं—पठानकोट में क्या हुआ ? मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन पांच आदमी तो आपने खुद माने हैं और छठा आदमी वहां पर बाद में मरा है । मैं बीकानेर भी गया था, वहां पर मैंने जो कानों से सुना उसे भी आपके सामने बयान करना चाहता हूं । वहां के रेलवे एम्पलाइज और उनकी फैमिली के लोग रेलवे ट्रैक पर गये और उन्होंने गाड़ी को रोकना चाहा ।

SHRI RANDHIR SINGH: Was he a railway employee who was run over?

SHRI SURAJ BHAN: Ex-Railway employee. His name was Chetan Das.

SHRI RANDHIR SINGH: Why was he an ex-employee?

श्री सूरज भान : यह बाद में बदला दूंगा । He might have been dismissed person जिस वक्त वे बीकानेर के रेलवे एम्पलाइज पिकेटिंग कर रहे थे, पुलिस ने वहां पर लाठी जार्ज किया । वहां पर एक मंजु बहन थीं, जिनकी उम्र 15–16 साल थी, लाठी लगने से उस बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने डी०एस०पी० के मुंह पर एक थप्पड़ मारा । उसने गलती की थी, डी०एस० पी० को थप्पड़ नहीं मारना चाहिये था, लेकिन डी०एस०पी० उसको गिरफ्तार कर सकते थे, डण्डे मार सकते थे, उस दरिन्दे ने उसको पिस्तौल से गोली मारी जिस वक्त वह लड़की नीचे गिरी उसने एक गोली और उस लड़की को मारी । इसी दौरान एक कृष्ण गोपाल नाम का एम्पलाई था उसने उस लड़की को उठाना चाहा, उस दरिन्दे ने उसको भी गोली मारी । कृष्ण गोपाल गोली खा कर वहीं मर जाता है लेकिन मंजू बहन दो गोली खाने के बाद अभी जिन्दा है ।

फीरोजपुर में क्या हुआ, इसी तरह से लाठी जार्ज किया गया, वहां पर एक क्लास 4 एम्पलाई था, जिसकी पत्नी अपनी छोटी बच्ची को गोद में लिये खड़ी थी । पुलिस ने उस पर लाठी चलाई, वह लाठी उस बहन को लगने के बजाय, उस बच्ची को लगी और वह बच्ची मर गयी । बाद में पुलिस ने उस कर्मचारी को मजबूर किया कि तुम यह कहो कि उस लड़की को बुखार था, यह न कहो कि उसको डण्डा लगा था । शमशान भूमि में उससे जबरदस्ती ऐसा लिखवा लिया गया । लेकिन खुशकिस्मती से फीरोजपुर अस्पताल इस बात का शाहिद है कि दो दिन पहले आंखों की बीमारी उस बच्चे के बारे में वहां पर दर्ज थी, लेकिन बुखार का नाम कहीं पर नहीं आता । मैं पुनाचा साहब और चव्हाण साहब से कहना चाहता हूं कि आप इसकी मैजिस्टीरियल इंक्वायरी कीजिये । बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं लेकिन मैं सिर्फ चन्द अलफाज का सहारा लेकर ही कहना चाहता हूं :

भंवरे ने तो एक फूल की निगहत लूटी
अफलास ने मुफलिस की मसर्रत लूटी ।

श्री चव्हाण ने डंडे का सहारा लेकर
कुछ बहनों का सुहाग और किस्मत लूटी ।।

. . . (व्यवधान) . . . .

तो जो स्ट्राइक हुई उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ ? आज हजारों मुलाजमीन नौकरी से बाहर हैं । मुझे खुशी हुई थी यह बात सुन कर कि रेलवे में एक पालिसी एडाप्ट की गई—जो कि पी० एन्ड टी० में नहीं थी—कि जो इत्तफाक से 19 तारीख को गैर-हाजिर थे, हड़ताल में शामिल नहीं किये गये थे, उनके लिये पुनाचा साहब ने यह इंस्ट्रक्शन्स इश्यु किये कि उनसे पूछ लिया जाये क्यों वे गैर-हाजिर थे । उनसे अर्जियां लेकर उनकी छुट्टियां सैंक्शन कर दी गईं । लेकिन आज अफसोस की बात है कि उनको छुट्टियां सैंक्शन करने के बाद भी

नौकरी से निकाला जा रहा है । रेलवे इस्टैब्लिशमेन्ट कोड का एक रूल 149 है जिसमें यह बात दी हुई है कि अगर कोई आदमी 48 घंटे से ज्यादा पुलिस के हाथ में रहे तब उसे सस्पेन्ड कर दिया जाये । तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन जो उन कर्मचारियों को इस तरह से टर्मिनेट कर रहा है वह क्या उस रूल का वायलेशन नहीं है ? हड़ताल के बाद अफसरान लोग अपने दिल का बुग्ज उन कर्मचारियों से निकाल रहे हैं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन में गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं, रेलवे की एफीशियन्सी को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप को उनके प्रति हमदर्दाना पालिसी अख्तियार करनी पड़ेगी । आज जो बाहर निकले हुए हैं उनके बगैर आप काम को ठीक तरह से नहीं चला पायेंगे । उनकी फेमिलीज पर हमदर्दी का रुख अख्तियार करके आप ने यह कहा भी कि कुछ कर्मचारियों की नोटिसेज वापिस ले ली जायं लेकिन जिनके नोटिसेज पहले ही समाप्त हो गये थे, उनका क्या कुसूर था, उनको क्यों सजा दी जा रही है ।

एक बात और है जिसको हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था कि कुछ अफसरान आज भी शेड्यूल्ड कास्ट्स से अपना बुग्ज निकाल रहे हैं । मैं इन्सटान्स देकर कोट करना चाहता हूं कि जगाधरी रेलवे स्टाफ में एक तुलसीराम नाम का एम्पलाई है, अकेला जिसने कि हड़ताल नहीं की थी लेकिन 18 तारीख को ही उसे सस्पेन्ड कर दिया गया । इसी तरह से सराय रोहिला में जो कुछ हुआ है वह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है । मैं यह बात मान सकता हूं कि हड़ताल को दबाने के लिये आर्डिनेन्स को निकाला गया था लेकिन यह किस क्लाज में लिखा हुआ था कि उनके गिरोह में जाकर उनको तंग किया जाये । इसी तरह से आप इसको जो कानूनी रूप दे रहे हैं कि अगर कोई कर्मचारी डेस्टिनेशन से पहले गाड़ी छोड़ेगा, मान लीजिये वह बीमार ही हो जाता है, उसके बाद भी उसे दो साल की सजा हो जायेगी । इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि रेलवे के काम को ठीक तरह से चलाने के लिये आप अपने मुलाजमीन के साथ हमदर्दी का रुख अख्तियार कीजिये, अफसरों के दिमाग में जो बुग्ज भरा हुआ है उसको दूर कीजिये और आप ने जो विक्टिमाइजेशन किया है उसको खत्म कीजिये । इस काम को करने के लिये आपको किसी और काले कानून की जरूरत नहीं है, जो पहले के कवानीन हैं वही काफी हैं ।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Mr. Speaker, I have very patiently heard some of the terms of abuses used against this Bill. All sorts of accusations have been made against the government for bringing forth such a Bill which seeks to place some restrictions on the freedom of the railway employees. I am quite aware that every law is aimed at curtailment of freedom, liberty and inherent rights. From that point of view any legislation which seeks to give more power to the government should be objected to, if it interferes with the freedom and liberty of the individual. In this particular case, what is the position?

I would just like to draw your attention to the instances where gheraos and bundhs were resorted to. My learned friend, Shrimati Tarkeshwari Sinha, mentioned some of the instances of how life was made impossible for some of the officers, officials and even the workers. May I ask Shri George Fernandes, Shri Banerjee and others, who are friends of labour, whether such activities are trade union activities?

I will also place before you certain other instances. A precarious law and other situation prevails in West Bengal from April 1967 onwards. It has nothing to do with trade union activities at all.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : गोविन्द मेनन वहां जा कर कह रहे हैं कि कानून तोड़ो ।

SHRI R. D. BHANDARE: If you raise the point, I will certainly join you in the limited sense of the term because nobody has any right to break and destroy the rule of law. The question is always raised by some of the Communists, more specially by Shri Nambiar, that since we are sovereign we have every right to destroy sovereignty. I shall never agree to that proposition.

The question is raised that when the Railway Act was orginally passed in 1890 and the Britishers did not feel the necessity of bringing forward such a measure, what compels or motivates the Government to bring forward such a legislation which, according to these friends, is a black legislation, a fascist legislation. I was, therefore, trying to quote the instances of isolated bundha and *hartals* on individual days, such as, Bengal Bundh and Assam Bundh. Bundhs is a disease with which we are affected. The opposition has started this disease.

When the language question was raised, agitation was carried on and the railway was the first casualty. Agitations connected with other issues, unrelated to railways at all, have affected the working of the railways and damaged the property of the railways. May I ask, and can we answer in all fairness, whether these are affected. The opposition has trade unionism?

We have to take into consideration the present conditions and the present situation. The situation when the Railway Act was passed in 1890 and the changed situation under which we are trying to amend the original Act have to be taken into consideration by us.

I do not know whether my learned friends have applied their mind to the Bill before the House. This Bill seeks to do two things. Firstly, it seeks to penalise abandonment of railway trains or rolling stock. Under clause 100A this is sought to be penalised. What is there in it which can be characterised as a black Act? If one is entrusted with the work of carrynig passengers in a train and if the train is abadoned in between railway stations or if one interfers with the railway lines, is it not right and roper on the part of Government to give protection to the passengers and to penalise those who are responsible for such an act? Thish is one. very small innocent provision.

The second thing which this Bill seeks to do is to penalise obstruction. That is under clause 100B. If the right is given to obstruct, to picket and to stop running trains, and the Government sleeps quietly, I think that Governemnt is not worth the name at all. If the Government is trying to penalishe such an act, then, they say, this is a black Act and this is a fascist Act. Except these two provisions, there is no third provision in the Bill at all. Where is the fascist tendency shown by the Governent in the Bill?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : इतना हम बोले आप नहीं सुने तो क्या करें। आप मुझे फिर इजाजत दें आधे घंटे बोलने की मैं समझा सकता हूं।

श्री रणधीर सिंह : जब पौन घंटे में नहीं समझा सके तो अब क्या समझाओगे ?

SHRI R. D. BHANDARE: I listened to my learned friend patiently. He dealt with two situations prevailing in the railway working, such as, gheraos, this and that and other before issuing of the Ordinance and the situation arising out of the 19th September strike. These were the two main planks on which he was dwelling for a long time.

So far as these two clauses are concerned, I do not think he has dealt with these clauses. But simply said that this is a black Act, this is a heinous Act, this is a shameless Act or this is a fascist Act. In Parliament when we deal with such a piece of legislation, we have got to pay more careful attention to it.

Now, Sir, we are giving more powers to the Railways, I therefore, want to make certain submissions in this regard. The powers must be exercised cautiously and must be tempered with justice. That is my first submission. My second submission is to reduce the punishment that is sought to be prescribed in the Bill. For an obstruction, or even for picketting, two years maximum punishment is prescribed. Should we not make one year as maximum punishment or penality? That is my second submission. When we are giving these powers to the Railways, the Railways should never forget the grievances of the workers and the grievances of the passengers. There are 40,000 to 50,000 temporary railway employees. Can we have such a proposition in a civilised society, in an advancing society, in a devloping society, where there are more than 50,000 casual workers? I have had an occasion to take a deputation of the temporary workers in the Western Railway. Do you know the reply given? The reply given was that they were casual labourers. How long can they be casual labourers? What a callous reply. I should say, not casual but callous reply? For 7 to 8 or even 10 years, they were casual labourers.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : 20 साल से और पांच लाख है ।

SHRI R. D. BHANDARE: Since I am very moderate in my speech, I am talking of averages. I am thankful to the hon. Member for the information.

So far as passengers' grievances are concerned, they are 'numerous' to use a very simple word. Nobody bothers whenever any complaint is lodged at the Railway Station or with the Station Master; nobody bothers to see whether there are lights in the bogies or whether there is water in the bogies or not. If we want to seek powers, we must also pay more attention to the grievances of both workers and passengers.

With these words, I support the Bill, and oppose the Resolution of Shri Fernandes.

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : स्पीकर साहब, पिछले टाइम जब 9 सितम्बर को एक आम हड़ताल का चर्चा हो रहा था तो मैंने अपोजीशन वाले भाइयों से दरख्वास्त की थी कि अगर आप कहते हैं कि यह सरकार भस्म हो जायेगी तो मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी कहां रहेगी ? डेमोक्रेसी भी भस्म हो जायेगी । दूसरी बात जो मैंने अपोजीशन वाले भाइयों से अर्ज की थी वह यह थी कि एक तरफ आप कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है कि वह हिन्दुस्तान को परेशान न करे और सेबोटतज न करे तो फिर अगर यह पहिया जाम हो जायेगा तो चाइना और पाकिस्तान के लिये आसानी हो जायेगी । मैं शुक्रगुजार हूं अपोजीशन वाले भाइयों का कि उन्होंने इस सरकार की बात को कुछ अपने तौर पर उस वक्त इस बात को टाल दिया और यह चाहा कि किसी तरह यूनियन गवर्नमेंट जो है वह समझ पाये और जो खुद ही कमीशन मुकर्रर करती है वह जो फैसले करते हैं उनकी रोशनी में मेंट्रल एम्प्लाईज को, खास तौर पर जो बेचारे गरीब हैं, छोटी तनख्वाह पाने वाले हैं उनकी बात सुन पाये ।

अब यह फिर 19 सितम्बर का चर्चा चला। सब जानते थे कि एक साल तक अपोजीशन वालों ने इसको रोके रखा, या मुनाजमीन ने अपनी अकल से इसको पोसपोन किया । जिसको क्रेडिट देना चाहें दे लीजिये, मुझे कोई ऐतराज नहीं । लेकिन स्पीकर साहब, जहां मेरे भाई जार्ज फरनेन्डीज कहते हैं कि वह ध्यान नहीं देते वहां अपनी तरफ भी कुछ कहें । श्री सिन्हा जी बहुत बोले, बहुत उन्होंने नुकसान बिनाये और उन्होंने कहा कि एक ही पब्लिक सेक्टर में कई गुना ज्यादा नुकसान एक, एक पब्लिक सेक्टर में आप लोग ने किया है अपनी इस प्लानिंग से और नालायक अफसरों को रख कर क्योंकि वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के परख्यू में नहीं हैं, उनको लगा कर जो करोड़ों का नुकसान किया है, और अगर मैं

[श्री अब्दुल गनी डार]

यह कहूं कि इससे कहीं ज्यादा आपके मिनिस्टरों ने फौरेन एक्सचेंज यों ही योरप और अमरीका की सैर करने के लिए खर्च किया है तो कोई ग़लत न होगा ।

सवाल यह होता है कि जितना रेवन्यू आये उसके मुताबिक खर्च किया जाये । मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि रेलवे के अफ़सरों के सैलून पर कितना खर्चा होता है । मैं मिनिस्टरों की नहीं कहता, रेलवे के जो अफ़सर हैं उनकी जो बोगी चलती है उस पर साल में कितना खर्च होता है जो मामूली से मामूली अफ़सर भी हैं । पार्लियामेंट के मेम्बर देश भर में सब से ज्यादा इज्जत के पात्र समझे जाते हैं इसलिये कि उहें 10 लाख भाई बहन चुन कर भेजते हैं, उनको एयर कंडीशन की इजाजत नहीं । पैसा दें तो सफर करे। लेकिन मामूली से मामूली अफ़सरों को इजाजत है कि वह ऐयर कंडीशन में जायें । ठीक है सरकार ने ऐसा किया मुझे कोई इसमें ज्यादा कहना नहीं है इसलिये कि सरकार मालिक है,हम मुलाजिम हैं भाई । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी उन्होंने गौर किया कि वह पार्लियामेंट के मेम्बरों की तौहीन क्यों करते हैं ? मामूली अफसरों को इजाजत दे देना और उसके मुकाबिले पार्लियामेंट के मेम्बरों को जिन्हें कि आखिर 10 लाख लोग चुन कर यहां भेजते हैं उन्हें इंकार कर देना यह चीज कहां तक मुनासिब है ?

17 hrs.

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रेल मंत्री महोदय को इस तरह का आर्डिनेंस लाने की ऐसी क्या जरूरत थी क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम था कि पार्लियामेंट थोड़े ही दिनों के बाद बैठने वाली है ? इस बारे में श्री सूरज भान की हिमायत करता हूं कि पुनाचा साहब में हिम्मत होती तो वह हाउस के सामने ऐसा मेजर मंजूरी के लिए लाते और इस तरह से बैक डोर से आर्डिनेंस पास न करवा लेते । वैसे भी वह अपनी ताकत के बल पर कोई भी चीज यहां से पास करवा सकते थे वरना वह हाउस के सामने कायदे से उसे लाते, हाउस में उसके लिए अपील करते और मंत्री महोदय हमारे दिमागों को छू सकते थे और अपनी बात कह कर हमारे दिलों पर भी दस्तक दे सकते थे और यह बतला सकते थे कि यह यह हमारी मजबूरियां हैं और इसलिये गवर्नमेंट को हाउस यह पावर्स दे । अगर पुनाचा साहब हाउस को कन्विंस करा देते तो हाउस से उन्हें यूनेनीमस सपोर्ट उस मेजर के लिए मिल सकती थी और यह हाउस खुशी-खुशी उन्हें वह अधिकार दे भी सकता था । लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने जो एक माकूल रास्ता उसे इस बारे में अपनाना चाहिए था वह नहीं अपनाया और बैक डोर से आर्डिनेंस पास करवा कर अब उसी को कानूनी रूप दिलवा रही है ।

चीन और पाकिस्तान से जंग के दौरान रेलवे के मुलाजिमों ने जिस मुस्तैदी के साथ अपने फर्ज को अंजाम दिया और उस नाजुक मौके पर जो उन्होंने देश की नुमायां खिदमत की थी उसकी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने और हमारी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहिब ने बेहद तारीफ़ की थी । उन्होंने उस वक्त यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि रेलवे मुलाजिम कितने देशभक्त हैं । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मंत्री महोदय उनको शक की नजर से देख रहे हैं और उन पर तरह तरह की बन्दिशें लगा रहे हैं । मेरा कहना है कि सरकार को मजदूरों की जायज मांगों को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए और उन्हें मान लेना चाहिए क्योंकि लेबर का असन्तुष्ट रहना एक ठीक बात नहीं है और वह देश के हित में नहीं होगा ।

इंडियन आयल कारपोरेशन बम्बई में एक पब्लिक सैक्टर की अंडरटेकिंग है । क्या मंत्री महोदय और ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों को इस बात का

इल्म है कि वहां के मजदूरों को 14 परसैंट बोनस देने की बात सोशलिस्ट्स मान गये, कम्युनिस्ट्स मान गये, जनसंघ वाले मान गये तमाम मजदूरों की जो असासियेशंस हैं वह भी इस को मान गईं लेकिन कांग्रेसियों की जो वहां पर बनाई हुई यूनियन है वह उसे नहीं मानी ? इसलिए मैं अपनी बहन को अर्ज करना चाहूंगा कि जब वह अपोजीशन वालों को लताड़ें और जहां उनका लताड़ना जायज हो उसे हम खुशी से मानने के लिए तैयार भी हैं लेकिन क्या खुद उन्होंने भी अपने दिल पर हाथ रख कर सोचा है कि क्या उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से अंजाम दिया है ? आज मेरी बहन ने अपोजीशन वालों को इसलिए लताड़ा है कि उनकी यूनियंस के कारण प्रोडक्शन में रुकावट पड़ी है और देश का नुक्सान हुआ है लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहूंगा कि उससे कहीं ज्यादा नुकसान पब्लिक सैक्टर में आपके अफसरों की नालायकी की वजह से हुआ है ।

यहां पर फारेन एक्सचेंज की वैस्टेज को रोकने और ज्यादा से ज्यादा उसे बचाने की भी उधर से बात की गई है तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अपोजीशन के मेम्बर्स के मुकाबले कांग्रेसी मेम्बरों की ज्यादा जिम्मेदारी रही है । मैं कहने पर मजबूर हूं कि बहुत से कांग्रेसी मेम्बर्स सैर करने जाते हैं और उसमें ज्यादा फारेन एक्सचेंज खर्च आता है बमुकाबले यह जो हमारे जोशी साहब या दूसरे अपोजीशन के मेम्बर साहबान मजदूरों और कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई तनख्वाहों और महंगाई भत्ते आदि की बात करते हैं । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है । कहने को आप हर जगह कहते नहीं थकते हैं कि यह जो निजी क्षेत्र के सरमायेदार हैं, पूंजीपति हैं, वह ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का ध्यान करें, उन्हें बढ़े हुए वेतन और महंगाई भत्ते आदि की सुविधाएं दें. लेकिन जब खुद उनको इस पर अमल करना होता है तो उससे मुकर जाते हैं । क्या कभी आपके दिमाग में यह बात आई कि हमें भी लेबर की जायज मांगों को मान लेना चाहिए ? अभी की बात है कि आई० ओ० सी० ने 14 परसैंट बोनस देने का ऐलान किया, सब मजदूरों की यूनियंस ने मान लिया लेकिन आपकी कांग्रेस की यूनियन ने उसे नहीं माना । इसके अलावा मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि जो बोनस आई० ओ० सी० ने देने का एलान किया क्या उतना बोनस आप भी देना कबूल करेंगे ? यह रेलवेज खाली उधर से चन्द दोस्तों की या हमारी बहन श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की नहीं है बल्कि वह सारे इस देश के हर एक भाई, बहन की है और जाहिर है कि रेलवेज में अगर नुकसान होता है तो वह सारे देश का नुकसान होता है। लेकिन नुकसान के नाम पर अगर इस तरीके से उन पर एक शक की नजर से देख कर उन पर तरह-तरह की नई, नई बंदिशें लगायी जाती हैं तो वह ग़ैरमुनासिब चीज होगी। चीन और पाकिस्तान की जंग के दौरान जिस तरीके से रेलवेज के मुलाजिमों ने, मजदूरों ने देशभक्ति का सबूत दिया, जिस तरीके से उन्होंने अपने सिर धार धड़ की बाजी लगाई, अपने काम में इतनी एफिशिएंसी दिखाई उस की तारीफ सरकार को करनी पड़ी और मुनासिब चीज यह होगी कि उनके मसले को हल करने के लिए कोई न कोई तदबीर करिये ।

जब मैं राज्य सभा में था और पंडित जी जिन्दा होते थे तो भी मैंने कहा था और आज फिर उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि सरकार का फर्ज है कि वह मजदूरों की जायज मांगों को मंजूर करे ताकि वह और भी दिल लगा कर और मेहनत से इस देश की पैदावार को बढ़ाये । अभी परसों श्री बाजपेयी ने जिक्र किया था कि अकेले काश्मीर पर सन 47 से लेकर आज तक 300 करोड़ रुपया खर्च किया गया जब कि बख्शी साहब ने कहा कि वह तीन सौ करोड़ नहीं बल्कि डेढ़ सौ करोड़ खर्च किया गया । लेकिन वहां पर हमने क्या देखा ? हम क़ाजी पीर के दर्रे तक पहुंच गये,

[श्री अब्दुल गनी दार]

अपने हजारों जवानों को शहीद करवाया, अपने बड़े बड़े फौजी अफसरों को शहीद करवाया लेकिन उसके बाद हम बन्दूकें लेकर घर वापिस आ गये । अब मैं कहना चाहता हूंकि मेरे भाई श्री रणधीर सिंह हरियाणा के यहां पर तशरीफ रखते हैं जहां का कि मैं भी एक सिपाही हूं, चाहे वह मेरे पंजाब के भाई हों, जहां कि मैंने जन्म लिया है और चाहे वह काश्मीर हो जहां कि मेरे बाप, दादे ने जन्म लिया, लेकिन आज मेरे साथ क्या बीत रही है ? अब काश्मीरी मुझे काश्मीरी नहीं मानते, पाकिस्तान वाले मुझे मुसलमान नहीं मानते और अफसोस इस बात का है कि जिस गांधी जी का मैं आजादी की लड़ाई का सिपाही रहा, आज उधर के ट्रेजरी बैंचज पर बैठने वाले भाई मुझे गैर समझते हैं, वह मुझे हिन्दुस्तानी मानने में हिचकते हैं और मुझे यहां पर पाकिस्तान का एजेंट कहा गया । यह किस्मत की बदनशीबी नहीं तो और क्या है कि जिस अब्दुल गनी ने अपने भाई को शहीद करवाया, आजादी की खातिर अपना घर, बार और दौलत सब कुछ न्योछावर कर दी उसे पाकिस्तान का आज एजेंट कहा जाता है लेकिन मुझे उन से कोई शिकायत नहीं है :

> "जाहिदे तंगनजर ने मुझे काफिर जाना
> और काफिर यह समझता है कि मुसलमां हूं मैं ।"

खैर, मुझे किसी से इसकी शिकायत नहीं है कि आज अपने ही लोग मुझे हिन्दुस्तानी मानने से हिचकते हैं बाकी जो हकीकत है वह तो इससे खत्म नहीं हो सकती ।

मैं पुनाचा साहब से अर्ज करूंगा कि वह रेलवे के मजदूरों की जो जायज मांगें हैं उन्हें मान लें, उनकी मश्किलात को दूर करें ताकि वह दिल लगा कर मेहनत से ड्यूटी दें । मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्होंने अगर मुल्क की एकोनोमी को गांधी जी के कहने के मुताबिक देश की दौलत का ठीक से बंटवारा नहीं किया, अभी जो भारी आर्थिक असमानता मौजूद है और मजदूरों, छोटे कर्मचारियों और बड़े अफसरान में 1 और 100 का वेतन में अन्तर है उस भारी फर्क को खत्म नहीं किया गया तो उनका यह शासन और प्रजातन्त्र नहीं चल पायेगा और यकीन जानिये हम और आप कुत्तों की तरह सड़कों पर मरे हुए दिखाई देंगे कोई दुनिया की ताकत वैसी हालत में हमें जिन्दा नहीं रख सकती है । मैं चाहता हूं कि मेरे कांग्रेसी भाई अपोजीशन के मेम्बरों और यूनियंस के कुछ जिम्मेदार लीडरों के साथ बैठ कर इस मसले पर सोच विचार करें और कोई मुनासिब हल निकालें । आज हम दुनिया भर के मकरूज हैं और हमने अपने देश को हर मुल्क के पास गिरवी रख दिया है । अगर आप चाहते हैं कि यह देश तरक्की करे, इस देश का प्रोडक्शन बढ़े तो आपको अपोजीशन के लीडर्स और यूनियंस के जिम्मेदार लीडरों को अपने पास बुला कर उनके साथ बैठ कर तबादला खयालात करें अपने मेजर्स के बारे में उन्हें कन्विंस करें तब उन्हें इसे पास कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही उनका उसमें कोआपरेशन भी मिल सकेगा । पुनाचा साहब से मेरी यह भी अर्ज है कि वह चाहे इंन ड्राइवर हो, खलासी हो या रेलवे का गार्ड हो उनकी देश-भक्ति के बारे में किसी तरह का भी शक अपने मनमें नहीं आने देना चाहिए । सारे रेलवे कर्मचारी यकीनी तौर पर देशभक्त हैं और इसलिए वह जो भी मेजर्स पास कराना चाहे उन्हें साफ तरीके से फ्रंट डोर से लायें इस तरह से आर्डिनेंस पास करा कर बैकडोर से कानून न पास करवायें । अगर वह चाहते है कि मेरे जैसे मेम्बर को उन्हें सपोर्ट मिले, मैं यहां पर दायें और बायें बाजू वालों को हरा कर एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुन कर आया हूं तो उन्हें इस तरह से बैकडोर से इसे नहीं करना चाहिए था । मैं अपनी बहन को और उधर के दोस्तों को अपील करना चाहता हूं कि वह ठंडे दिल से सोचें कि

आखिर आज क्या हालत उनकी हो गई है ? कल तक जिस गांधी जी और कांग्रेस के नाम पर देश के किसी भी कोने से एक गरीब से गरीब आदमी एक राजा और रईस के मुकाबले में जीत जाया करता था, जिस कांग्रेस का नाम सुनते ही बड़ों-बड़ों के पांव कांप जाया करते थे, आज यह हालत हो गई है कि उसी कांग्रेस को केवल 39 परसेंट वोट्स मिले हैं और मैं अपने दोस्तों को चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर अब भी वह नहीं संभले और उन्होंने अपने को नहीं सुधारा तो उन्हें और भी बुरा दिन देखने को मिलने वाला है क्योंकि आज तो अपोजीशन पार्टीज अलग अलग काम कर रही हैं, उनका हक़ीकत में कोई युनाइटेड फ्रंट नहीं है लेकिन आगे चल कर उनकी समझ में आयेगा और वह आप के मुकाबले में एक में संगठित होकर खड़ी हो जायेंगी । मैं श्री पुनाचा से अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस बिल को पास कराने का इसरार करने के बजाय यूनियन वालों को बुला लें और उनके साथ बैठ कर कोई एक रास्ता निकालें । इस तरह गोलियां चला कर और नौकरियों से बर्खास्त कर के उन गरीब कर्मचारियों को बरबाद करना और उनके परिवारों को बर्बाद करना न तो आपके हित में है और न ही वह देश के हित में है। कांग्रेस की खोई हुई इज्जत गांधी जी के बतलाये हुए रास्ते पर चलने में ही हासिल हो सकती है और मुझे यकीन है कि चाहे वह जोशी साहब हों चाहे और कोई कम्युनिस्ट भाई हों अगर आप उनका सहयोग हासिल करेंगे तो वह आपसे मिल कर काम करने में इंकार नहीं करेंगे और वह आपको फिर प्यार करेंगे । आपके साथ चलने में फख्र करेंगे, लेकिन अगर यहाँ राजे-रजवाड़ों का ही राज्य रहा तो आप मेरे कहने पर मेरी बहन खफा न हों कि :

Munde Kuriya da Jhund yara katha ho gya Hakumat da chalanaki thatha ho gya.

Is it a joke to run the Government?

यह कोई मजाक नहीं है ।

> जहाँबानी से है दुश्वार कारे जहाँबीनीं
> जिगरखूं हो तो चश्मे दिल में होती है
> नजर पैदा ।

खुदा के लिये आप अपने दिलों पर हाथ रख कर सोचिये । आप एक बिल नहीं दस बिल पास कीजिये, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बजाय इस बिल के रखने के कोई न कोई रास्ता निकालें । सदर साहब आप हमारे भी सदर रहे हैं और मैं आपका वालेंटियर रहा हूं । मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वह कोई रास्ता निकालें । हमारे श्री जोशी वही जोशी हैं जिन्होंने वतन के लिये बरसहा बरस कैद काटी है, बड़े मुहब्बे वतन रहे हैं । अपोजीशन वालों में भी अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों भाई ऐसे हैं, अगर आप खफा न हों, आप से कहीं ज्यादा कैद काटी है । मेरा यक़ीन है कि बहुत कम आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी तरह अपने खान्दान से तीन जानें दी होंगी। मैं ने 21 बरस से गोलियां खाई हैं । सोलह बरस से मुस्लिम लीग की गालियां खाता रहा, वह जूते लगाते रहे, महाशय कहते रहे और 21 बरस से कांग्रेस वालों की गालियां खा रहा हूँ । लेकिन मुझे न उनका दुःख था और न इनका दुःख है । मैं दोनों को अंगूठा दिखलाता हूं क्योंकि मैं सब बात कहता हूं । मैं फिर वही बात कहूंगा जो पिछले साल 9 तारीख को कही थी। आप बगैर उनसे कोई बात तय किये हुए कोई रास्ता निकालिये । अगर आप ऐसा रास्ता अख्त्यार नहीं करेंगे तो यकीनन हुकूमत का पहिया जाम होगा, वह चलेगा नहीं । देश का नुकसान होगा, लेकिन इस में आप का पहिया भी जाम होगा, मेरा भी होगा और पार्लियामेंट के मेम्बरों का भी जाम होगा, और बाहर देख लीजियेगा कि कुत्तों की तरह मरे पड़े होंगे ।

شری عبدالغنی ڈار - (گڑگاؤں) :
ڈپٹی سپیکر صاحب - پہلے ٹائم جب
تو سسٹم کو ایک عام ہوتا تھا

[شری عبدالغنی ڈار]

چرچا ہو رہا تھا تو میں نے اپوزیشن والے بھائیوں سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار بھسم ہو جائے گی تو میں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی کہاں رہے گی؟ ڈیموکریسی بھی بھسم ہو جائے گی - دوسری بات جو میں نے اپوزیشن والے بھائیوں سے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان سے خطرہ ہے کہ وہ ہندوستان کو پریشان نہ کرے - سیبوتوبج نہ کرے تو پھر اگر یہ پہیہ جام ہو جائے گا تو چین اور پاکستان کے لئے تو آسانی ہو جائے گی - میں شکر گزار ہوں اپوزیشن والے بھائیوں کا کہ انہوں نے اس سرکار کی بات کو اچھے طور پر اس وقت ٹال دیا - اور یہ چاہا کہ کسی طرح یونین گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھ پائے اور جو خود بھی کمیشن مقرر کرتی ہے وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کی روشنی میں سینٹرل ایمپلائز کو خاص طور پر جو بیچارے غریب ہیں - چھوٹی تنخواہ پانے والے ہیں ان کی بات سن پائے -

اب یہ پھر انیس ستمبر کا چرچا چلا - سب جانتے ہیں کہ ایک سال تک اپوزیشن والوں نے اس کو روکے رکھا - یا ملازمین نے اپنی دل سے اس کو پوسٹپون کیا جس کو کریڈٹ دینا چاہیں دے لیجئے - مجھے کوئی اعتراض نہیں - لیکن اسپیکر صاحب جہاں میرے بھائی جارج فرنینڈیز کہتے ہیں کہ وہ دھیان نہیں دیتے وہاں اپنی طرف بھی کچھ کہیں - شری سنہا جی بہت بولے بہت انہوں نے نقصان گنائے اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی پبلک سیکٹر میں کئی گنا زیادہ نقصان آپ لوگوں نے کیا اپنی آل پلاننگ سے اور نالائق افسروں کو رکھ کر - کیونکہ وہ یونین پبلک سروس کمیشن کے پرویو میں نہیں ہیں - ان کو لگا کر کروڑوں کا نقصان کیا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ اس سے کہیں زیادہ آپ کے منسٹروں نے فارین ایکسچینج یوں ہی یورپ اور امریکہ کی سیر کرنے کے لئے خرچ کیا ہے تو کوئی غلط نہ ہو گا -

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا ریوینیو آئے اس کے مطابق خرچ کیا جائے - میں آپ کے دوارہ اپنی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریلوے کے افسروں کے سیلون پر کتنا خرچ ہوتا ہے - میں منسٹروں کی نہیں کہتا - ریلوے کے جو معمولی سے معمولی افسر ہیں انکی بوگی چلتی ہے اس پر سال میں کتنا خرچ ہوتا ہے - پارلیمنٹ کے ممبر دیش بھر میں سب سے زیادہ عزت کے پاتر

سمجھے جاتے ہیں اس لئے کہ انہیں دس لاکھ بھائی بہن چن کر بھیجتے ہیں - ان کو ایجیٹیشن کی اجازت نہیں - پیسہ دیں تو سفر کریں - لیکن معمولی سے معمولی افسروں کو اجازت کیسے کہ وہ ایجیٹیشن میں جائیں - ٹھیک ہے سرکار نے ایسا کیا مجھے کوئی اس میں زیادہ کہنا نہیں ہے - اس لئے کہ سرکار مالک ہے اور ہم ملازم ہیں بھائی -

لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی انہوں نے غور کیا کہ وہ پارلیامنٹ کے ممبروں کی توہین کیوں کرتے ہیں - معمولی افسروں کو اجازت دے دیں اور اس کے مقابلے پارلیامنٹ کے ممبروں کو جنہیں کہ آخر ۱۰ لاکھ لوگ چن کر یہاں بھیجتے ہیں انہیں اٹھا کر دیکھا یہ چیز کہاں تک مناسب ہے -

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریل ملٹری میوٹنی کو اس طرح کا آرڈیننس لانے کی ایسی کیا ضرورت تھی کیونکہ انہیں پتہ ہی معلوم تھا کہ پارلیامنٹ تھوڑے ہی دنوں کے بعد بیٹھنے والی ہے - اس بارے میں میں شری سورج بھان کی حمایت کرتا ہوں کہ پناچا صاحب میں ہمت ہوتی تو وہ اس ہاؤس کے سامنے ایسا میژر منظوری کے لئے لاتے اور اس طرح سے بیک ڈور سے آرڈیننس پاس نہ کروا لیتے - ویسے بھی وہ اپنی طاقت

کے بل پر کوئی بھی چیز یہاں سے پاس کروا سکتے تھے ورنہ وہ ہاؤس کے سامنے قاعدے سے اسے لاتے - ہاؤس میں اس کے لئے اپیل کرتے اور ملٹری میوٹنی ہمارے دماغوں کو چھو سکتے تھے اور اپنی بات کہہ کر ہمارے دلوں پر بھی قبضہ کر سکتے تھے اور یہ بتلا سکتے تھے کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں اور اس لئے گورنمنٹ کو ہاؤس یہ پاورس دے - اگر پناچا صاحب ہاؤس کو کنونس کرا دیتے تو ہاؤس سے انہیں یونینیمس سپورٹ اس چیز کے لئے مل سکتی تھی اور یہ ہاؤس خوشی خوشی انہیں وہ ادھیکار دے بھی سکتا تھا - لیکن مجھے افسوس ہے کہ سرکار نے جو ایک معقول راستہ اسے اس بارے میں اپنانا چاہئے تھا وہ نہیں اپنایا اور بیک ڈور سے آرڈیننس پاس کروا کر اب اسی کو قانونی روپ دلوا رہی ہے -

چین اور پاکستان سے جنگ کے دوران ریلوے کے ملازموں نے جس مستعدی کے ساتھ اپنے فرض کو انجام دیا اور اس نازک موقعے پر جو انہوں نے دیش کی نمایاں خدمت کی تھی اس کی سورگیہ لال بہادر شاستری نے اور ہماری موجودہ پرائم منسٹر صاحبہ نے بیحد تعریف کی تھی - انہوں نے اس وقت یہ پوری طرح سے ثابت کر دیا تھا کہ ریلوے ملازم کتنے دیش بھگت ہیں - لیکن افسوس کے ساتھ کہنا

[شری عبدالغنی ڈار]

پڑ رہا ہے کہ آج ملٹری مینڈیٹ ان کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ان پر طرح طرح کی بندھن لگا رہے ہیں - میرا کہنا ہے کہ سرکار کو مزدوروں کی جائز مانگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئیے اور انہیں مان لینا چاہئیے کیونکہ لیبر کا اسٹیٹمنٹ رہنا ایک ٹھیک بات نہیں ہے اور وہ دیش کے ہت میں نہیں ہوگا۔

انڈین آئل کارپوریشن بمبئی میں ایک پبلک سیکٹر کی انڈرٹیکنگ ہے۔ کیا ملٹری مینڈیٹ اور ٹریژری بینچز پر بیٹھنے والے ماننیہ سدسیوں کو اس بات کا علم ہے کہ وہاں کے مزدوروں کو ۱۴ پرسینٹ بونس دینے کی بات سوشلسٹس مان گئے - کمیونسٹس مان گئے - جن سنگھ والے مان گئے - تمام مزدوروں کی جو وہاں ایسوسی ایشنس ہیں وہ بھی اس کو مان گئیں لیکن کانگریسیوں کی جو پر بھائو ہوئی یونین ہے وہ اسے نہیں مانی - اسلئے میں اپنی بہن کو عرض کرنا چاہونگا کہ جب وہ اپوزیشن والوں کو لتاڑیں اور جہاں ان کا لتاڑنا جائز ہو اسے ہم خوشی سے ماننے کے لئے تیار بھی ہیں لیکن کہ خود انہوں نے بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے کہ کیا انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے انجام

دیا ہے - آج میری بہن نے اپوزیشن والوں کو اس لئے لتاڑا ہے کہ ان کی یونینس کے کارن پروڈکشن میں رکاوٹ پڑی ہے اور دیش کا نقصان ہوا ہے لیکن میں انہیں بتلانا چاہونگا کہ اس سے کہیں زیادہ نقصان پبلک سیکٹر میں آپ کے افسروں کی نالائقی کی وجہ سے ہوا ہے -

یہاں پر فارین ایکسچینج کی ویسٹیج کو روکنے اور زیادہ سے زیادہ اسے بچانے کی بھی ادھر سے بات کی گئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کے ممبرس کے مقابلے کانگریسی ممبروں کی زیادہ ذمہ داری رہی ہے - میں کہنے پر مجبور ہوں کہ بہت سے کانگریسی ممبر، سیر کرنے جاتے ہیں اور اس میں زیادہ فارین ایکسچینج خرچ آتا ہے بمقابلے یہ جو ہمارے جوشی صاحب یا دوسرے اپوزیشن کے ممبر صاحبان مزدوروں اور کرمچاریوں کے لئے بڑھی ہوئی تنخواہوں اور مہنگائی بھتے آدی کی بات کرتے ہیں - مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سرکار کی کہنے اور کرنے میں انتر ہے - کہنے

آپ ہر جگہ کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ یہ جو نجی چھیتر کے سرمائے دار ہیں - پونجی پتی ہیں - وہ زیادہ سے زیادہ مزدوروں کا دھیان کریں انہیں

بڑھتے ہوئے ویتن اور مہنگائی بھتے آدی کی سویدھائیں دیں لیکن جب خود ان کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے تو اس سے مکر جاتے ہیں - کیا کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمیں بھی لیبر کی جائز مانگوں کو مان لینا چاہیئے - ابھی کی بات ہے کہ آئی او سی نے ۱۴ پرسینٹ بونس دینے کا اعلان کیا سب مزدوروں کی یونینس نے مان لیا لیکن آپ کی کانگریس کی یونین نے اسے نہیں مانا - اس کے علاوہ میں ریلوے منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بونس آئی او سی نے دینے کا اعلان کیا اتنا بونس آپ بھی دینا قبول کریں گے - یہ ریلویز خالی ادھر کے چند دوستوں کی یا ہماری بہن شریمتی تارکیشوری سنہا کی نہیں ہے بلکہ وہ اس دیش کے ہر ایک بھائی - بہن کی ہے اور ظاہر ہے کہ ریلویز میں اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ سارے دیش کا نقصان ہے لیکن نقصان کے نام پر اگر اس طریقے سے ان پر ایک شک کی نظر سے دیکھ کر ان پر طرح طرح کی نئی - نئی بندشیں لگائی جاتی ہیں تو وہ غیر مناسب چیز ہوگی - چین اور پاکستان کی جنگ کے دوران جس طریقے سے ریلویز کے ملازموں نے دیش بھگتی کا ثبوت دیا جس طریقے سے انہوں نے اپنے سر اور دھڑ کی بازی لگائی اپنے کام میں اتنی ایفیشنسی دکھائی اس کی تعریف سرکار کو کرنی پڑی اور مناسب چیز یہ ہوگی کہ ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی تدبیر کریئے -

جب میں راج سبھا میں تھا اور پنڈت جی زندہ ہوتے تھے تو بھی میں نے کہا تھا اور آج پھر ایسی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ سرکار کا فرض ہے کہ وہ مزدوروں کی جائز مانگوں کو منظور کرے تاکہ وہ اور بھی دل لگا کر اور محنت سے اس دیش کی پیداوار کو بڑھائیں - ابھی پرسوں شری واجپئی نے ذکر کیا تھا کہ اکیلے کشمیر پر سنہ ۴۸ سے لیکر آج تک ۳۰۰ کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا جبکہ بخشی صاحب نے کہا کہ وہ تین سو کروڑ نہیں بلکہ تیرہ سو کروڑ خرچ کیا گیا - لیکن وہاں پر ہم نے کیا دیکھا - ہم حاجی پیر کے درے تک پہنچ گئے اپنے ہزاروں جوانوں کو شہید کروایا - اپنے بڑے بڑے فوجی افسروں کو شہید کروایا لیکن اس کے بعد ہم بندوقیں لیکر کے واپس آ گئے - اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی شری رندھیر سنگھ ہریانے کے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں کہوں گا کہ میں بھی ایک سپاہی ہوں چاہے وہ میرے پنجاب کے بھائی ہوں جہاں کہ میں نے جنم لیا ہے اور چاہے وہ کشمیر ہو جہاں کہ میرے باپ دادا نے جنم لیا لیکن آج میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے - اب کشمیری ہندو کشمیری نہیں مانتے - پاکستان والے مجھے مسلمان نہیں مانتے اور افسوس اس بات کا

[شری عبدالغنی ڈار]

ہے کہ جس گاندھی جی کا میں آزادی کی لڑائی کا سپاہی رہا آج ادھر کے ٹریژری بینچیز پر بیٹھنے والے بھائی مجھے غیر سمجھتے ہیں وہ مجھے ہندوستانی ماننے سے جھجکتے ہیں اور مجھے یہاں پر پاکستان کا ایجنٹ کہا گیا - یہ قسمت کی بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ جس عبدالغنی نے اپنے بھائی کو شہید کروایا - آزادی کی خاطر اپنا گھر بار اور دولت سب کچھ نیوچھاور کر دی اسے پاکستان کا آج ایجنٹ کہا جاتا ہے لیکن مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے -

ادھر تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں -

پھر مجھے کسی سے اس کی شکایت نہیں ہے کہ آج ایسے ہی لوگ مجھے ہندوستانی ماننے سے ہچکتے ہیں باقی جو حقیقت ہے وہ تو اس سے ختم نہیں ہو سکتی -

میں پناچا صاحب سے عرض کرونگا کہ وہ ریلوے کے مزدوروں کی جو جائز مانگیں ہیں انہیں مان لیں ان کی مشکلات کو دور کریں تاکہ وہ دل لگا کر محنت سے ڈیوٹی دیں - میں یہ چیتاونی دینا چاہتا ہوں انہوں نے اگر ملک کی ایکونامی کو گاندھی جی کے کہنے کے مطابق نہیں کی دولت کا ٹھیک سے بٹوارا نہیں کیا ابھی جو بھاری آرتھک اسمانتا موجود ہے اور مزدوروں - چھوٹے کرمچاریوں اور بڑے افسران میں ایک اور سو کا ویتن میں انتر ہے اس بھاری فرق کو ختم نہیں کیا تو ان کا یہ شاسن اور پرجاتنتر چل نہیں پائیگا اور یقین جانئے ہم اور آپ کتوں کی طرح سڑکوں پر مرے ہوئے دکھائی دینگے کوئی دنیا کی طاقت ایسی حالت میں ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتی ہے - میں چاہتا ہوں کہ میرے کانگریسی بھائی اپوزیشن کے ممبروں اور یونینز کے کچھ ذمہ دار لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے پر سوچ وچار کریں اور کوئی مناسب حل نکالیں - آج ہم دنیا بھر کے مقروض ہیں اور ہم نے اپنے دیش کو ہر ملک کے پاس گروی رکھ دیا ہے - اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیش ترقی کرے اس دیش کا پروڈکشن بڑھے تو آپ کو اپوزیشن کے لیڈرس اور یونینز کے ذمہ دار لیڈروں کو اپنے پاس بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیالات کریں - اپنے ممبرس کے بارے میں انہیں کنونس کریں تب انہیں اسے پاس کرانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی اور ساتھ ہی ان کا اس میں کوآپریشن بھی مل سکیگا - پناچا صاحب سے میری یہ بھی عرض ہے کہ وہ چاہے انجن ڈرائیور ہوں خلاصی ہو یا

ریلوے کا گارڈ ہو ان کی دیش بھکتی
کے بارے میں کسی طرح کا بھی شک
اپنے من میں نہیں آنے دینا چاہئے -
سارے ریلوے کرمچاری پچھلی طور پر
دیش بھکت ہیں اور اس لئے وہ جو
بھی میمورس پاس کرانا چاہیں انہیں
صاف طریقے سے فرنٹ ڈور سے لائیں
اس طرح سے آرڈیننس پاس کرا کر
بیک ڈور سے قانون نہ پاس کروائیں -
اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرے جیسے
ممبر کی انہیں سپورٹ ملے - میں
یہاں پر دائیں اور بائیں بازو والوں
کو ہرا کر ایک آزاد امیدوار کی
حیثیت سے چن کر آیا ہوں تو انہیں
اس طرح سے بیک ڈور سے اسے نہیں
کرنا چاہئے تھا - میں اپنی بہن
کو اور ادھر کے دوستوں کو
اپیل کرنا چاہتے ہوں کہ وہ ٹھنڈے دل
سے سوچیں کہ آخر آج کیا حالت ان
کی ہو گئی ہے - کل تک جس گاندھی
جی اور کانگریس کے نام پر دیش کے
کسی بھی کونے سے ایک غریب سے
غریب آدمی ایک راجہ اور رئیس کے
مقابلے میں جیت جایا کرتا تھا -
جس کانگریس کا نام سنتے ہی بڑوں
بڑوں کے پاؤں کانپ جایا کرتے تھے آج یہ
حالت ہوئی کہ اسی کانگریس کو
کیول ۳۹ پرسنٹ ووٹ ملے ہیں اور
میں اپنے دوستوں کو چیتاونی دینا
چاہوں گا کہ اگر اب بھی وہ نہیں
سنبھلے اور انہوں نے اپنے کو نہیں سدھارا
تو انہیں اور بھی برا دن دیکھنے کو
ملنے والا ہے کیونکہ آج تو اپوزیشن پارٹیز
الگ الگ کام کر رہی ہیں ان کا
حقیقت میں کوئی یونائٹڈ فرنٹ
نہیں ہے لیکن آگے چل کر ان کی
سمجھ میں آئیگا اور وہ آپ کے مقابلے
میں سنگٹھت ہو کر کھڑی ہو جائینگی -
میں شری پناچا سے ادب کے ساتھ
عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بل کو
پاس کرانے کا اصرار کرنے کے بجائے یونین
والوں کو بلا لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر
وہ ایک راستہ نکالیں - اس طرح
گولیاں چلا کر اور نوکریوں سے برخاست کر
کے ان غریب کرمچاریوں کو برباد کرنا
اور ان کے پریواروں کو برباد کرنا نہ تو
آپ کے ہت میں ہے اور نہ ہی وہ
دیش کے ہت میں ہے - کانگریس کی
کھوئی ہوئی عزت گاندھی جی کے بتلائے
ہوئے راستے پر چلنے سے ہی حاصل ہو
سکتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ چاہے
وہ جوشی صاحب ہوں چاہے اور کوئی
کمیونسٹ بھائی ہوں اگر آپ ان کا
سہیوگ حاصل کرینگے تو وہ آپ سے مل
کر کام کرنے میں انکار نہیں کرینگے اور
وہ آپ کو پھر پیار کرینگے -

آپ کے ساتھ چلنے میں فخر
کریں گے - لیکن اگر یہاں راجے رجواڑوں
کا ہی راج رہا تو میرے کہنے پر
میری بہن خفا نہ ہوں کہ—

Munde Kuria de jhund yara katha ho gya.

[شری عبدالغنی ڈار]

Hakuma da chalana ki thatha ho gya

Is it a joke to run the Government?

یہ کوئی مذاق نہیں ہے -

جہانبانی سے ہے دشوار کارِ جہاں بینی -
جگر خوں ہو تو چشمِ دل میں ہوتی ہے نظر پیدا -

خدا کے لئے آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے - آپ ایک بل نہیں دس بل پاس کیجئے - لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس بل کے رکھنے کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں - صدر صاحب آپ ہمارے بھی صدر رہے ہیں اور میں آپ کا والنٹیر رہا ہوں - میں آپ کے دوارا منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کوئی راستہ نکالیں - ہمارے شری جوشی وہی جوشی ہیں جنہوں نے وطن کے لئے برسہا برس قید کاٹی ہے - بڑے محب وطن رہے ہیں - اپوزیشن والوں میں بھی اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں بھائی ایسے ہیں - اگر آپ خفا نہ ہوں - آپ سے ہم میں زیادہ قید کاٹی ہے - میرا یقین ہے کہ بہت کم آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے میری طرح اپنے خاندان سے تین جانیں دی ہوں گی - میں نے ۲۱ برس سے گالیاں کھائی ہیں - سولہ برس سے مسلم لیگ کی گالیاں کھاتا رہا - وہ جوتے لگاتے رہے - سہاتے کھاتے رہے اور ۲۱ برس سے کانگریس والوں کی گالیاں کھا رہا ہوں - لیکن مجھے نہ ان کا دکھ تھا اور نہ ان کا دکھ ہے - میں دونوں کو انگوٹھا دکھلاتا ہوں کیونکہ میں سچ بات کہتا ہوں - میں پھر وہی بات کہوں گا جو پچھلے سال ۹ تاریخ کو کہی تھی - آپ بغیر ان سے کوئی بات طے کئے ہوئے کوئی راستہ نکالئے - اگر آپ ایسا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو یقیناً حکومت کا پہیہ جام ہوگا - وہ چلے گا نہیں - دیش کا نقصان ہوگا - لیکن اس میں آپ کا بھی پہیہ جام ہوگا - میرا بھی ہوگا اور پارلیامنٹ کے ممبروں کا بھی جام ہوگا - اور باہر دیکھ لیجئےگا کہ کتوں کی طرح مرے پڑے ہوں گے -]

SHRI SAMINATHAN* (Gopichettipalayam): Mr Speaker, Sir, on behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, I wish to express our deep resentment at and protest against the Indian Railways (Amendment) Bill which has been brought forward by the hon. Railway Minister. I wish to express our deepest resentment and protest to this measure at the outest. The reason for this, Sir, is that there are certain basic fundamental rights which have been enshrined in our constitution, which have been guaranteed by the constitution, but which are being taken away by this measure. So many lakhs of employees are affected by this measure. Under the proposed amendment 100A, if the employee refuses to do the work he will be awarded 2 years imprisonment and fine of Rs. 500. Both punishments will be given. According to the amendment 100B, if a railway servant, when on duty or otherwise, obstructs any train or if he engages in a strike, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may

*The original speech was deliveredin Tamil.

extend to five hundred rupees, or with both.

Sir, if the Railway servants engaged in unlawful activities, the Railway Act itself has got ample provisions to deal with them. In the Nineth chapter, there are already powers enumerated to deal with which unawful activities and such powers are existing already. Those powers are quite sufficient to deal with such situations. Therefore, these amendments which have been brought forward by Clauses 100A and 100B appears unnecessary.

For so many years, so many lakhs of railway employees have been pressing various just demands, but this Government has not cared to redress those genuine demands. The Railway Board and the Railway Minister have not taken any steps to redress their just and genuine grievances. No steps have been taken by this Government so far to accede to their legitimate demands. The right path of wisdom on the part of the Government would be to use their goodwill and labour for constructive activities and not to curb their activities by more and more powers being taken by the amending Bills of this nature. By such amendments, by such powers, no solution will be found. There is no use of having such amendments. There have been various amendments which have been brought forward from time to time. But I wish to bring to the notice of the hon. Minister that is is only by giving consideration for the needs of labour and by enlisting their goodwill that they can do things and not by curbing the activities of labour by assuming more and more powers. There are various categories of railway employees, who are working in the loco sheds, who are working as gang coolies, ticket collectors, station masters etc. There are various just and reasonable demands which have been voiced by these and other categories of workmen in the Raiways. But, it is only the advice of the big bureaucrats who earn thousands of rupees in the Railway Ministry which is taken by the Railway Minister, and not the just and reasonable requests of lakhs and lakhs of ordinary railway employees. Instead of thinking on the lines of appointing a Commission for the purpose of examining the ways and means of avoiding accidents and how to increase more and more amenities for the travelling public they are putting more and more restrictions on the workmen. The Railway fares are unduly high and they are beyond the capacity of the people to pay. In order to find out how the fares could be reduced, they could appoint a Commission. The Commission may also go into the matter of giving better amenities for the travelling public and removal of the just and reasonable grievances of railwaymen. Their just and reasonable demands should be taken into consideration and needful done by the Government for their redresseal. Instead of that, the Government is bent upon encouraging On the part of the employees feelings of ill-will and hatred towards the Government. There is no wisdom in such a step. I am not able to understand this step on the part of the Government.

Since many lakhs of railway employees are affected by this Amending Bill, and since already there are enough powers under the Government, I, on behalf of the DMK party, express my emphatic protest against this measure. I request that the hon. Railway Minister should withdraw this Bill. Thank you.

श्री एस० एम० जोगी (पूना) : मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आप ने माननीय सदस्य को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार दिया है । वह बहुत थोड़ा बोले हैं । अगर उसी समय उनकी स्पीच की अंग्रेजी करने की व्यवस्था कर दी जाय तो सब लोग उसको समझ सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : कल ट्रांस्लेशन मिलेगा, आज नहीं ।

श्री एस० एम० जोशी : अगर अभी हो सकता . . .

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं हो सकता है ।

श्री एम० एम० जोशी : अगर आप चार आदमी रख लें तो हो सकता है, इसके लिये आप को कुछ आदमियों को नौकरी में रखना चाहिये ।

MR. SPEAKER: You can discuss it with me. If it is possible, not 4 people, even 10 people I am prepared to employ. We have examined it and it is not so easily possible.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन रेलवे संशोधन विधेयक पर विचार कर रहा है । इस विधेयक के सम्बन्ध में अभी बहुत से माननीय सदस्य ने बहस में भाग लेते हुए बहुत सी बातें कहीं । कुछ सदस्यों ने रेल के मजदूरों की क्या दिक्कतें हैं और रेलवे स्ट्राइक के बारे में सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं क्या उनमें पुलिस द्वारा ज्यादती की गई, इस तरफ ध्यान दिलाया, कुछ दूसरे सम्मानित सदस्यों ने अपनी कहानी सुनाई । पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह संशोधन एक साधारण सा संशोधन है फिर भी इसका विरोध बहुत जोर शोर से किया जा रहा है ; मेरी मान्यता में इसके विरोध के पीछे राजनीतिक कारण प्रमुख हैं ।

यह विधेयक जो रेलवे अध्यादेश का स्थान ले रहा है, ऐसे मौके पर आ रहा है जबकि रेलवे अध्यादेश सरकार को मजबूर होकर जारी करना पड़ा, उस समय पर जब सरकार के सामने स्ट्राइक वालों के लिये सहानभति का कोई रास्ता नहीं रहा, जब समझ बूझ की सारी बात खत्म हो गई, और सरकारी श्रमिक, रेलवे के मजदूर कुछ राजनीतिक नेताओं की हाथ की कठपुतली बन कर इस बात के लिये तैयार हो गये कि वे 19 सितम्बर को हड़ताल करेंगे ।

इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहा गया है । सरकार ने यह अध्यादेश ऐसे मौके पर जारी किया जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी और ऐसे मौके पर सरकार को यह अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिये था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करने के लिये समय ही तब होता है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता है । अगर पार्लियामेंट का सेशन होता तो अध्यादेश की जरूरत नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि स्ट्राइक करवाने वाले नेताओं ने ऐसे मौके पर स्ट्राइक करने की योजना बनाई जबकि समझ बूझ के सारे रास्ते बन्द हो गए थे । इस वास्ते सरकार को मजबूर होकर इस अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा । चूंकि इस अध्यादेश की वजह से कर्मचारियों की हड़ताल असफल हो गई इस वास्ते इस सफलता से चिन्तित होकर और इनके बहकावे में जो चन्द कर्मचारी आ गए उनको सहारा देने के लिए उनको सन्तोष देने के लिए आज इस सदन में बार बार यह दलील पेश की जाती है कि इस अध्यादेश के जरिये से सरकार श्रमिक कानून को अपने हाथ में ले रही है, श्रम संगठनों को खत्म करना चाहती है और सरकार श्रमिकों की सुविधायें की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश का मतलब क्या था ? क्योंकर यह अध्यादेश जारी किया गया ? क्या ऐसे मौके पर जबकि श्रमिक संगठनों का उद्देश्य यह है हो कि देश की शासन व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए ? उसको ठप्प होने दिया जाए तो सरक

ऐसी अवस्था को बैठी देखती रहे ? श्रमिक संगठन रहने चाहिये और प्रजातन्त्र में कोई भी सरकार श्रमिकों के कल्याण में उतनी ही इंटरेस्टिड होती है, उतना ही हिस्सा लेती है, उतनी ही दिलचस्पी लेती है जितनी कि सदन के दूसरे माननीय सदस्य या कोई और साथी लेना चाहते हैं । प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सरकार का काम सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहे, उसमें किसी तरह के रोड़े न अटकाये जायें, किसी तरह की रुकावट पैदा न हो । लेकिन हमारे दोस्तों का तो यह मंशा था जैसा कि अभी भाषणों में भी जाहिर किया गया है कि रेल कर्मचारियों की हड़ताल करवा कर शासन व्यवस्था को ठप्प किया जाये । अभी उन्होंने यह बताया है कि इटली में पहली दफा एक समाजवादी प्रधान मन्त्री को चुनने का मौका दिया गया है वहां पर 48 घंटे की हड़ताल करवा कर । क्या हमारे दोस्त भी यहां पर 24 घंटे की हड़ताल करवा कर ऐसा ही कुछ करना चाहते थे ?

हमारे देश में प्रजातन्त्र है और प्रजातन्त्र में सरकार बदलने का अधिकार केवल मात्र वोट के जरिये से ही लोगों को प्राप्त है । अगर इस तरह की हड़ताल के जरिये, इस तरह के प्रदर्शनों के जरिये देश के अन्दर अव्यवस्था पैदा करने की और देश का शासन व्यवस्था को ठप्प करने की, देश की शासन अपने हाथ में लेने की कुचेष्टा की जाए तो सरकार का यह फर्ज हो जाता है किसी भी जिम्मेदार और समझदार सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि ऐसी कुचेष्टा को वह रोके इस कुचेष्टा को वह विफल करे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों की यह निश्चित योजना थी कि इस देश के प्रशासन को ठप्प कर दिया जाय । इनके द्वारा एक पोस्ट अखबार निकाला जाता है । इसके कुछ हिस्से पढ़ कर मैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं : इनका नारा क्या था ? मैंने इसको समझने की कोशिश की है और जैसा मैं इसे समझा हूं उस तरह से मैंने दूसरों को भी समझाने की कोशिश की है और यहां भी मैं करना चाहता हूं । इन लोगों ने जो नारा दिया पोस्ट अखबार के जरिये से वह काबिले गौर है । मैं इसको पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं ।

POST, the journal of the All-India Postal Employees Union—Class III (CGS). में यह छपा था:

"The massive movement of the empoyees likely to take place on 19-9-68 will unleash powerful forces forcibly to shake them to their foundations and eject them from their ivory tower to grasp the realities. On the backs of the people they rose to power and when they are forcibly made to come down they will have an ignominious fall, a fall shattering their hypocrisy to smithereens."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ इसमें लिखा गया है, जो कुछ इन्होंने नारा दिया कि टेक फुल चार्ज आफ गवर्नमेंट्स प्रापर्टी एण्ड वैल्युएबल्ज क्या यह नारा पीसफुल स्ट्राइक का है, क्या इस नारे को देकर ये लोग राज्य को और शासन को कायम रखना चाहते थे, क्या ये शासन व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे ? श्रमिकों का यह अधिकार है कि वे अपने कल्याण की बातें सोचें, उनको यह अधिकार है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब भी श्रमिक संगठनों के अन्दर इस तरह के प्रोफैशनल राजनीतिक नेता घुस जाते हैं या जब कभी श्रमिक संगठनों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में चला जाता है, जिनका धंधा राजनीति है और जो उनके वोट के आधार पर चुन कर आना चाहते हैं तो वे लोग श्रमिकों को गुमराह करना चाहते हैं, तब सरकार को मजबूर होकर ऐसे कानूनों

[श्री नवल किशोर शर्मा]

का सहारा लेना पड़ता है ताकि देश की सुरक्षा खतरे में न पड़े । यह परम आवश्यक था कि इस तरह का आर्डिनेंस सरकार द्वारा जारी किया जाए । ऐसा करके सरकार ने सही कदम उठाया । इसी आर्डिनेंस को यह सदन विधेयक का रूप देने जा रहा है । यह विधेयक अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधेयक है ।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा जहां पर सरकार उन रेल कर्मचारियों के कामों पर रोक लगाना चाहती है जो कि गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, रेल के चक्के को जाम करना चाहते हैं, रेलवे में तथा देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, वहां यह कानून उन लोगों पर भी पाबन्दी लगाता है जो विद्यार्थियों के नाम पर, छात्रों के आन्दोलन के नाम पर या भाषा के नाम पर तथा दूसरे नामों पर इस देश में दंगे कराते रहते हैं । मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत से ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनसे यह पता चलता है कि इस देश में इन लोगों ने, इन दंगाइयों ने इस राष्ट्र की बहुत सी सम्पत्ति को, रेलवे की सम्पत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया है । क्या यह सही है कि रेलवे के एक पैसेंजर को, रेलवे के ट्रैफिक को कोई भी आदमी भाषा के नाम पर या किसी राजनीतिक पहलू को लेकर उसके नाम पर या किसी दूसरे तरीके से हिंसा के जरिये से असुविधा पहुंचाये ? मैं आपका ध्यान रेलवे कानून की दफा 27 की तरफ दिलाना चाहता हूं । यह दफा कहती है कि किसी भी पैसेंजर को, किसी भी रेलवे ट्रफिक को बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में रेलवे सुविधा प्रदान करेगी । अगर इस तरह से पिकिटिंग होती है, झगड़े होते हैं, रेलवे लाइन पर बैठ कर रेलों को चलने से रोका जाता है, जंगल के अन्दर बारह बजे रात ड्राइवर रेलवे को छोड़ कर खड़ा हो जाता है, तो क्या उसका यह कदम सही है और अगर सही नहीं है तो क्या इस धारा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये । अब यह 27 धारा साफ है तो सरकार का यह फ़र्ज हो जाता है कि जब इस प्रकार की असुविधा पैदा की जाती है और कानून की जिस धारा का मंशा खत्म करने की कोशिश की जाती है तो उसके बारे में मजीद सोच करके नए तरीके से उसको एमेंड करने की व्यवस्था वह करे ।

यह कानून केवल मात्र रेलवे के नौकरों के लिए नहीं है बल्कि उन सब लोगों के लिए है जो रेलवे व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, जो रेलों के सुचारु संचालन में रुकावट पैदा करना चाहते हैं । पिछले डेढ़ साल में हमारे देश में इस तरह की बहुत सी घटनायें हुई हैं और हम सब लोगों ने इन घटनाओं के प्रति चिन्ता प्रकट की है । ऐसी अवस्था में क्या यह हमारा फर्ज नहीं है कि हम उन चिन्ताओं के निराकरण के प्रयत्न करें ।

बहुत सी बातें यहां कही गई हैं । रेलवे लाज जो हैं, जो सर्विस रूल्ज हैं उनकी तरफ तवज्जह दिलाते हुए यह कहा गया है कि उन रूल्ज में पहले से ही इस तरह की व्यवस्थायें हैं । मैं इसको मानता हूं । लेकिन साधारण रेलवे एम्प्लायीज के अलावा दूसरे भी लोग ऐसे कामों को करते हैं और उनको रोकने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था इस कानून में नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक अपने आप में एक बहुत जरूरी विधेयक है ।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में श्रमिज व्यवस्था के बारे में हम को पुनर्विचार करना पड़ेगा । हमें सोचना होगा कि हमारे देश की श्रमिक व्यवस्था का जो ढांचा है क्या यह उसी तरह से उन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में भी चले जहां उन अंडरटेकिंग्ज की सरकार मालिक है, जिनका मालिक देश है, जो राष्ट्र की सम्पत्ति है, जिसका मास्टर देश का प्रत्येक नागरिक है, जिसमें काम करने वाले श्रमिक किसी प्राइवेट व्यक्ति के प्राफिट के लिए, उसके मुनाफे के

के लिए या किसी एक पूंजीपति के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि वे राष्ट्र के लिए काम करते हैं ? हमारा फर्ज है कि हम ऐसे मजदूरों में, ऐसे लोगों के अन्दर जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं ऐसी भावना पैदा करें जिससे वे राष्ट्र हित में चलने वाले इन कामों में रोड़े बनने के बजाय सहायक बन सकें । रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक अंडरटेकिंग है । हमारा फर्ज है कि इस अंडरटेकिंग के जरिये हम देश का उत्पादन बढ़ायें, देश की जनता को सुविधायें पहुंचाएं, उनके सुख दुख का ध्यान रखें । लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि राजस्थान में क्या हुआ । वहां ड्राउट की वजह से सैकड़ों हजारों लोगों का जीवन खतरे में है । वहां पर चारे की कमी है जिसकी वजह से गौ माताओं पर संकट आया हुआ है । लेकिन उस सब की परवाह रेलवे एम्प्लायीज ने नहीं की । ऐसे समय पर भी इन्होंने सोचा कि स्ट्राइक की जानी चाहिये अपने पेट के लिए, छोटी सी बातों के लिए स्ट्राइक पर जाना चाहिये और हजारों लोगों का अगर जीवन खतरे में भी है तो भी उनके जीवन की कोई परवाह नहीं की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विधेयक है जिसका हम सब लोगों को समर्थन करना चाहिये । मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सदन भी इसका समर्थन करेगा और इसको पास कर देगा ।

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

MILITARY PREPARATIONS BY PAKISTAN

डा० सुशीला नायर (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले हफ्ते इस सदन के बहुत से सदस्यों ने पाकिस्तान की चौकसार फौजी तैयारियों के बारे में एक सवाल पूछा था । सुरक्षा मन्त्री ने उस सवाल का जो जवाब दिया, उससे हम लोगों को सन्तोष नहीं है । उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि

> "Pakistan continues military activity of various kinds including construction of defence structures and conducting of training exercises across the border."

लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि

> "There is, however, nothing to indicate that there has been a significant increase in these activities recently."

अखबारों से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान टर्की और यूरोप के कई देशों से सैकड़ों टैंक लाने की कोशिश कर रहा है और वह अमरीका रूस और यूरोप के देशों से सब तरह की युद्ध की सामग्री प्राप्त कर रहा है । क्या यह प्रवृत्ति इस बात की द्योतक नहीं है, क्या इससे अनुमान नहीं होता है कि पाकिस्तान अपनी फौजी तैयारियां बढ़ा रहा है ?

एक माननीय सदस्य ने उस दिन अयूब, साहब के भाषण में से एक उद्धरण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तानियों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ शान्ति से रहना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ, और सारे विश्व के साथ, शान्ति से रहना चाहता है, लेकिन इस दिशा में उसकी हर एक कोशिश के बावजूद अगर कोई हमारे साथ शैतानी करे, अगर हमारी आंख निकालने की कोशिश करे, तो शान्ति बनाए रखने के लिए हम उसे अपनी आंख तो नहीं निकलने दे सकते । चीन के साथ दोस्ती रखने के इरादे को सामने रखते हुए हमने पुराने जमाने में अपनी सुरक्षा की बहुत ज्यादा परवाह नहीं की और उस का हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ । यह हमारी खुशकिस्मती थी कि जब पिछली दफा पाकिस्तान ने हमारे साथ